जून , 2023, वर्ष : 44 अंक : 06 www.indiatibet.net

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका

# तिब्बत देश

ऑस्ट्रेलिया के नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित करते सिक्योंग पेन्पा छेरिंग।

मूल्य :10 रू , वार्षिक : 100 रू

जून, 2023, वर्ष : 44 अंक : 06

# तिब्बत देश

तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका पहली बार 1979 में प्रकाशित तिब्बत के बारे में सही जानकारी के साथ हर महीने आपके हाथो में

तिब्बत हाउस संचालित नालंदा पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों के बैठक मे परम पवन दलाई लामा।

**प्रधान संपादक**
जमयंग दोरजी

**सलाहकार संपादक**
प्रो. श्यामनाथ मिश्र , डा. अतुल कुमार

**प्रबंध संपादक**
तेनजिन जोरदेन, ताशी देकि

**वितरण प्रबंधक**
छोन्यी छेरिंग

**संपादकीय एवं प्रकाशन कार्यालय :**
भारत तिब्बत समन्वय केन्द्र
एच -१० लाजपत नगर -३
नई दिल्ली -११००२४, भारत

तिब्बत देश में प्रकाशित विचरों से संपादक, प्रकाशक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है।

इसमें प्रकाशित सामग्री का उपयोग अन्यत्र किया जा सकता है। कृपया तिब्बत देश का उल्लेख अवश्य करें ।

## समाचार -


- तिब्बत हाउस संचालित नालंदा पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ बैठक 1
- परम पावन दलाई लामा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से सहानुभूति व्यक्त की 2
- सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने ऑस्ट्रेलिया के नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित किया 3
- सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने अपनी पहली यात्रा के समापन से पहले न्यूजीलैंड के सांसदों से मुलाकात की 4
- सिक्योंग ने सिडनी में आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान तिब्बत के अंदर की स्थिति पर प्रकाश डाला 5
- सिडनी में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग का आधिकारिक कार्यक्रम संपन्न 6
- ब्रिटिश द्वीपों, नॉर्डिक- बाल्टिक क्षेत्रों और पोलैंड में तिब्बत पर काम कर रहे नागरिक समूह स्वीडन में पहली क्षेत्रीय बैठक करेंगे 7
- भारत-तिब्बत मैत्री संघ की सिरमौर इकाई के सदस्यों से मिलीं कलोन नोरजिन डोल्मा 8
- तिब्बती नेताओं ने नई दिल्ली में विश्व के शीर्ष राजनयिकों से मुलाकात की 9
- धर्मशाला के दो दिवसीय दौरे पर आए उच्चस्तरीय यूएसएड प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व से मुलाकात की 10
- भारत-तिब्बत मैत्री संघ की सिरमौर इकाई के सदस्यों से मिलीं कलोन नोरजिन डोल्मा 11
- प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने टोक्यो में तियानमेन नरसंहार की वर्षगांठ में भाग लिया 12


## समाचार -


- चीनी संपर्क अधिकारी सुल्ट्रिम ग्यात्सो ने तिब्बती अस्तित्व के चीनीकरण पर प्रकाश डाला 13
- लद्दाख की कार्यवाहक सीआरओ ने सांसद जामयांग छेरिंग नामग्याल और एडवोकेट ताशी ग्याल्सन से शिष्टाचार भेंट की 14
- ऑस्ट्रेलियाई संसद की प्रतिनिधि सभा और सीनेट ने सिक्योंग पेन्पा छेरिंग को सम्मानित किया 15
- कुल मिलाकर शी जिनपिंग एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक भाषा का दृष्टिकोण रखते है
  सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने शी जिनपिंग के शासन में चीन की तिब्बत नीति पर अपने विचार रखे 16
- कनाडाई सांसदों ने तिब्बत में आवासीय स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया 17
- कनाडा के ओटावा की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान वाशिंगटन डीसी स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ने कनाडाई सांसदों से मुलाकात की 18
- तिब्बती मठों की तलाशी के दौरान चीनी अधिकारी भिक्षुओं से दलाई लामा से संबंध त्याग की घोषणा करने को कह रहे हैं
  यह कदम उस आदेश के अनुरूप है, जिसके तहत लोकसेवकों को निर्वासित आध्यात्मिक नेता के साथ संबंध तोड़ना आवश्यक तय किया गया है। 19
- चीन ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो-सोलर प्लांट से विस्थापित तिब्बतियों को मुआवजा देने से इनकार किया खानाबदोशों ने चीनी सरकार से शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ 20
- यूएनएचआरसी ५३वां सत्र : यूएन के इतर समारोह में तिब्बत में दमन की स्थिति का मुद्दा उठाया गया 21
- भारत-तिब्बत समन्वय संघ ने हरियाणा के सोनीपत में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 'चिंतन २०२३' आयोजित की 22


मुद्रक एवं प्रकाशक जमयांग दोरजी द्वारा प्रेम गुलाटी , डोली ऑफसेट प्रिंटर्स , डी -१५२ , एफ. एफ. सी. ओखला , नई दिल्ली -११००२० से मुद्रीत

तिब्बत के बारे में नियमित जानकारी के लिए भारत - तिब्बत समन्वय केन्द्र की वेबसाइट
www.indiatibet.net
Email:
indiatibet7@gmail.com


५३वां संयुक्त राष्ट्र एचआरसी सत्र : संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त और सदस्य देशों ने तिब्बत में चीन द्वारा मानवाधिकारों के हनन की ओर ध्यान आकर्षित किया 23

तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने बेल्जियम में तिब्बत के पक्ष रखे 24

**अपनी बात**

# ◆ सराहनीय है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तिब्बत के लिये बढ़ता सहयोग

तिब्बत के सिक्योंग (राज्याध्यक्ष) पेंपा छेरिंग की न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा से विस्तारवादी चीन बेचैन हो गया है। जून, 2023 में सम्पन्न इस सफल यात्रा के दौरान पेंपा छेरिंग का दोनों देशो की सीनेट तथा हाउस ऑफ रिप्रजेन्टेटिव्स में गर्मजोषी से स्वागत किया गया। कई सांसदों ने साम्यवादी चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध करते हुए तिब्बती संघर्ष को भरपूर सहायता एवं समर्थन जारी रखने की घोषणा की। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने स्पष्ट कर दिया कि वे चीनी दबाव में आये बिना तिब्बती संघर्ष के साथ रहेंगे। ज्ञातव्य है कि चीन सरकार तिब्बती आंदोलन के समर्थक देशो को गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी देती रहती है।

भारत एवं चीन के बीच स्वतंत्र तिब्बत एक बफर स्टेट (मध्यस्थ राज्य) था। तब भारत की सीमा स्वतंत्र तिब्बत से जुड़ी थी, न कि चीन से। उस समय चीन की सीमा भी तिब्बत से सटी थी, न कि भारत से। स्वतंत्र तिब्बत पर साम्राज्यवादी चीन ने 1959 में अवैध नियंत्रण कर लिया। परिणामतः चीन की सीमा भारत से जुड़ गई। तभी भारत-तिब्बत सीमा की जगह भारत-चीन सीमा अस्तित्व में आ गई। इससे चीन-तिब्बत सीमा का अस्तित्व भी मिट गया। आज भी हमारी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस 1959 की भारत-तिब्बत सीमा की याद दिलाती रहती है। इसी प्रकार चीन की दीवार बताती है कि चीन की सीमा चीन की दीवार है। बाकी चीनी क्षेत्र चीन का अवैध कब्जा है।

चीन सरकार ऐतिहासिक प्रमाणों को विकृत एवं परिवर्तित करके तिब्बत को चीन का अभिन्न अंग बताती है। उसके अनुसार तिब्बत का सवाल चीन का घरेलू सवाल है तथा इसमें किसी भी अन्य देश को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। निर्वासित तिब्बत सरकार की कशाग (संसद) द्वारा संचालित तिब्बत समर्थन (एडवोकेसी) अभियान ने मौलिक प्रमाणों एवं तथ्यों को प्रकाषित-प्रचारित-प्रसारित करके चीन को बेनकाब कर दिया है। इस अभियान के लिये गठित स्वैच्छिक तिब्बत समर्थन समूह में युवापीढ़ी की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सिक्योंग पेंपा छेरिंग की प्रेरणा, प्रोत्साहन और अपील से प्रभावित तिब्बती युवावर्ग की तिब्बत समर्थन अभियान में उत्तरोत्तर बढ़ती भागीदारी अभिनंदनीय है। चीन की बेचैनी का कारण यही है। तिब्बत के विषय में उसके भ्रामक दुष्प्रचार पर कोई विष्वास नहीं कर रहा। विष्वभर में तिब्बत समर्थन अभियान के माध्यम से स्पष्ट है कि लोकतांत्रिक मूल्यों, मानवीय आदर्षों तथा अंतरराष्ट्रीय कानून की अवहेलना कर चीन ने तिब्बत पर अवैध कब्जा कर रखा है।

न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे तिब्बतियों द्वारा कई जगह पेंपा छेरिंग के हार्दिक स्वागत से भी प्रमाणित है कि विभिन्न देशों में निवास कर रहे तिब्बती छोटे-छोटे शहरों में भी चीन को सफलतापूर्वक बेनकाब कर रहे हैं। सिक्योंग पेंपा छेरिंग ने अपनी यात्रा के दौरान दोनों देशो में जनप्रतिनिधियों, विचारकों, पत्रकारों, नीति निर्माताओं, अधिकारियों तथा तिब्बतियों एवं तिब्बत समर्थकों से तिब्बत समस्या के समाधान हेतु चीन पर दबाव बढ़ाने की अपील की। उन्होंने सभी कार्यक्रमों में चीन द्वारा जारी मानवाधिकार हनन, प्राकृतिक संसाधनों के विनाष, पर्यावरण प्रदूषण तथा तिब्बती पहचान को मिटाने के चीनी षड्यंत्र पर विस्तार से प्रकाष डाला। उन्होंने आग्रह किया कि चीन के साथ द्विपक्षीय वार्ता के समय सभी देश तिब्बत के सवाल को गंभीरता से उठायें।

तिब्बती सिक्योंग पेंपा छेरिंग ने बताया कि कशाग द्वारा तिब्बती समुदाय के लिये कई कल्याणकारी कार्यक्रम भारत सहित विष्व के अनेक देशो में जारी हैं। उन्होंने बलपूर्वक कहा कि सर्वाधिक जरूरी है मध्यममार्ग नीति के अनुरूप तिब्बत को चीन के अंदर ही वास्तविक स्वायत्तता मिले। चीन के संविधान और राष्ट्रीयता कानून के अनुसार चीन सरकार अंतरराष्ट्रीय संबंध और प्रतिरक्षा विभाग अपने पास रखे। वह शिक्षा, कृषि आदि अन्य सभी विभाग तिब्बत सरकार को सौंप दे। इससे चीन की भौगोलिक एकता-अंखडता सुरक्षित रहेगी और तिब्बती समुदाय को स्वषासन का अधिकार मिल जायेगा।

चीन के लिये उचित है कि वह तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता प्रदान कर दे। तथाकथित स्वायत्तता उसने पहले से दे रखी है। इसके अंतर्गत उसने तिब्बत के भौगोलिक क्षेत्रों में काट-छाँट कर उन्हें चीन का भूभाग बना दिया है। शेष क्षेत्रों में भी चीनी प्रशासन और पहचान प्रभावी है। तिब्बती अपनी पहचान तथा पकड़ छोड़ने के लिये बाध्य हैं। यही कारण है कि तिब्बत में चीन के प्रति विरोध हमेशा बढ़ता जा रहा है। चीन के विरूद्ध ऐसा ही विरोध ताइवान, मंगोलिया, इस्ट तुर्किस्तान एवं हांगकांग में भी उफान पर है। इससे बचाव का एकमात्र उपाय यही है कि चीन अपने पड़ोसी देशो में उपनिवेशवादी नीति समाप्त करे। भारत भी यही चाहता है।

तिब्बत के समर्थन में विश्व जनमत के अनुरूप भारत को अपनी महत्वपूर्ण भूमिका खुलकर निभानी होगी। भारत की कूटनीतिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक कदम बढ़ाने होंगे। तथाकथित हिन्दी चीनी भाई-भाई, पंचशील और सफेद कबूतर उड़ाने के मायाजाल से निकलकर हम भारत को लगातार शक्तिशाली बनायें। चीन ने 1962 में भारत के बड़े भूभाग को हथिया लिया था। उसके बाद भी उसने कई भारतीय भूभागों को हथियाने की कोशिश की है। हमारा सर्वसम्मत संसदीय संकल्प और राष्ट्रीय कर्तव्य है कि हम भारतीय भूभाग को चीनी चंगुल से मुक्त करायें। इसके लिये और तिब्बत समस्या के हल के लिये भारत की शक्ति को हर तरह से बढ़ाना जरूरी है। चीन को जवाब उसी की भाषा में देना होगा। विश्वशांति के लिये भी ऐसा करना जरूरी है।

प्रो0 श्यामनाथ मिश्र
पत्रकार एवं अध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खेतड़ी (राजस्थान)

मो.-9079352370, 8764060406
E-mail & Facebook: - shyamnathji@gmail.com

# ◆ तिब्बत हाउस संचालित नालंदा पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ बैठक

dalailama.com०२ जून, २०२३

**थेगछेन छोएलिंग, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, भारत।** आज ०२ जून की सुबह परम पावन दलाई लामा लगातार बेमौसम की कंपकंपी वाली ठंड और बरसात के बावजूद लगभग ५०० छात्रों से मिले। इन छात्रों ने हाल ही में नालंदा मास्टर्स कोर्स, नालंदा डिप्लोमा कोर्स या नई दिल्ली स्थित तिब्बत हाउस द्वारा प्रस्तुत नालंदा डिप्लोमा कोर्स से स्नातक किया है या वर्तमान में इन कोर्स में अध्ययन कर रहे हैं। गेशे दोरजी दमदुल द्वारा तिब्बत हाउस से चलाए जा रहे इन पाठ्यक्रमों में वर्तमान में ९८ देशों के ४००० से अधिक छात्र नामांकित हैं। डॉ कावेरी गिल ने तिब्बत हाउस के छात्रों और कर्मचारियों का परम पावन से परिचय कराया और उनके लिए गेशे दोरजी दमदुल जैसी क्षमता के शिक्षक भेजने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।

गेशे दोरजी दमदुल ने परम पावन को नालंदा पाठ्यक्रमों से संबंधित तीन मूर्तियाँ और एक फ्रेम किया हुआ पोस्टर भेंट किया। उन्होंने परम पावन, सिक्योंग पेन्पा छेरिंग, और तिब्बत हाउस के उपाध्यक्ष और भारत की पूर्व विदेश सचिव डॉ. निरुपमा राव के प्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त किया।

उन्होंने परम पावन से कहा, 'हम सभी आपके छात्र हैं। हम आपसे सीखना चाहते हैं। पिछली सदी में महात्मा गांधी अहिंसा के प्रबल पुजारी थे, लेकिन वर्तमान सदी में परम पावन करुणा के प्रबल समर्थक हैं।'उन्होंने उन सभी को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने तिब्बत हाउस में कार्यक्रम को सफल बनाने में मदद की और विशेष रूप से तेम्पा छेरिंग, जेट्सन पेमा और डोबूम रिनपोछे का उल्लेख किया। उन्होंने भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के उदार समर्थन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके समर्थन के बिना यह कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता था।

उन्होंने कहा, 'हम करुणा और ज्ञान की उस मशाल को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे परम पावन ने मौलिक मानवीय मूल्यों को बढ़ावा देकर जलाए रखा है। तेलो तुल्कु की मदद से हमने हाल ही में नालंदा पाठ्यक्रम से संबंधित गतिविधियों को रूसी भाषी लोगों तक पहुंचाया है।

हम उम्मीद करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सार्वभौमिक नैतिकता को अपनाया जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि विश्व के नेता परम पावन से सीखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य शांति, स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त करना है। दुनिया आपके नेतृत्व के प्रकाश का लुत्फ उठाती रहे।

नालंदा पाठ्यक्रम के मुख्य समन्वयक श्री दीपेश ठक्कर ने मुख्य अतिथियों का स्वागत किया और बताया कि तिब्बत हाउस ने अपने छात्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप क्रमशः छह साल, १४ महीने और डेढ़ महीने के क्रमश लंबे, मध्यम और छोटे पाठ्यक्रम तैयार किए हैं। नालंदा मास्टर्स के छह वर्षीय पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले पहले समूह ने हाल ही में उत्तीर्णता हासिल की है।

ठक्कर ने टिप्पणी की कि गेशे दोरजी दमदुल एक मार्गदर्शक प्रकाश थे। उन्होंने कहा कि छात्रों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या दोगुनी है और छात्रों की आयु १४ से ८० वर्ष के बीच है। उन्होंने जोर देकर कहा कि 'हमारा उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार करना नहीं बल्कि उस ज्ञान को साझा करना है जो अधिक से अधिक लोगों को खुश, दयालु इंसान बनने में मदद करने वाला है। हम परम पावन को हम तहेदिल से धन्यवाद देते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं।'तिब्बती लोगों ने सदियों से नालंदा परंपरा के संरक्षण के लिए खुद को समर्पित किया है। हम प्रार्थना करते हैं कि परम पावन दीर्घायु हों और अनुरोध करते हैं कि हम उनसे ज्ञान प्राप्त करते रहें।'

परम पावन ने मुस्कुराते हुए श्रोताओं को संबोधित किया, 'सुप्रभात मेरे धर्म भाइयों और बहनों। हमारे पास मिलने का यह अच्छा अवसर है। इसे आयोजित करने के लिए काम करने वाले सभी को धन्यवाद। इतने लंबे समय तक निर्वासन में रहने के दौरान मैं इस तरह के अवसरों पर कई अलग-अलग लोगों से मिला हूं और हमने एक-दूसरे से सीखा है।

यूरोप आदि देशों में बौद्ध धर्म का प्रसार नहीं हुआ है। अतीत में उन देशों में रहने वाले लोग केवल अपनी धार्मिक परंपराओं पर ध्यान देते थे, लेकिन आजकल कई अन्य परंपराओं, खासकर भारत की आध्यात्मिक परंपराओं में भी रुचि ले रहे हैं।

नालंदा परंपरा का सार अनुष्ठान और प्रार्थना नहीं, बल्कि चित्त को बदलने में सक्षम होना है। हमने तिब्बत हाउस की स्थापना की ताकि लोग इसके बारे में और जान सकें। तिब्बत हमेशा से बौद्ध नहीं था। वह सातवीं और आठवीं शताब्दी में, जब हमारे राजाओं ने रुचि ली तब बौद्ध देश बन गया। राजा सोंगत्सेन गम्पो ने देवनागरी वर्णमाला पर आधारित एक नई तिब्बती लिपि का ईजाद किया। नतीजतन, जब राजा ठिसोंग देचेन के निमंत्रण पर शांतरक्षित हिम की भूमि पर आए, तो उन्होंने यह सिफारिश की कि भारतीय बौद्ध साहित्य का तिब्बती में अनुवाद किया जाए। परिणाम कांग्यूर और तेंग्यूर संग्रह सामने है।

'राजा ठिसोंग देचेन ने शांतरक्षित के शिष्य कमलशील और ह्वाशांग चीनी भिक्षुओं के प्रतिनिधियों के बीच शास्त्रार्थ का भी आयोजन कराया था। उन्होंने फैसला दिया कि कमलशील बुद्ध की शिक्षाओं की व्यापक व्याख्या करने में सक्षम हैं, जबकि चीनी भिक्षुओं का ध्यान मुख्य रूप से ध्यान पर था।'

शांतरक्षित और कमलशील ने अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण स्थापित किया, जिसमें पढ़ने और सुनने के द्वारा समझ विकसित करना, चिंतन के माध्यम से उस समझ को गहरा करना, कारण और तर्क का उपयोग करना और ध्यान में इसका अनुभव प्राप्त करना शामिल था।

'समय के साथ, सेरा, गदेन, डेपुंग और ताशी ल्हुन्पो के महान मठ शिक्षा के केंद्र बन गए जहां भिक्षुओं ने महान ग्रंथों का अध्ययन किया और फिर तर्क का उपयोग करके यह पता लगाया कि उन्होंने शास्त्रार्थ में क्या सीखा था। बौद्ध धर्म आज कई देशों में फल-फूल रहा है, लेकिन केवल तिब्बती बौद्ध धर्म ही बुद्ध की शिक्षाओं की व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करता है। इसके अलावा, जब वैज्ञानिक इस बारे में अधिक जानना चाहते हैं कि बौद्ध धर्म चित्त के प्रकार्य के बारे में क्या कहता है, तो वे तिब्बती परंपरा की ओर ही देखते हैं।

'ऐसा इसलिए है, क्योंकि हम कारण और तर्क पर भरोसा करते हैं कि हम

धर्मनिरपेक्ष नैतिकता के संदर्भ में दुनिया के कल्याण के लिए योगदान करने में सक्षम हैं।'

परम पावन ने उल्लेख किया कि वे अंतर्धार्मिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने के लिए कितने उत्सुक हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि विभिन्न आध्यात्मिक परंपराएं काफी भिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों को अपना सकती हैं, पर उन सभी में जो समान है वह एक अच्छे हृदय के विकास पर बल देता है। उन्होंने कहा कि भारत एक अनुकरणीय राष्ट्र है जहां दुनिया की सभी प्रमुख धार्मिक परंपराएं साथ-साथ फल-फूल रही हैं। उन्होंने दोहराया कि नालंदा पाठ्यक्रमों के बारे में जो पहले ही कहा जा चुका है, वह लोगों के बौद्ध बनने के बारे में बहुत कम और नालंदा परंपरा से जो वे सीख सकते हैं, उसके साथ अपने स्वयं के अभ्यास और विश्वास को समृद्ध करने में सक्षम होने के बारे में अधिक है।

यद्यपि तिब्बत हाउस के प्रतिनिधियों ने अनुरोध किया था कि परम पावन जे चोंखापा के 'मार्ग के तीन प्रमुख पहलू' पर अपना प्रवचन दें लेकिन उन्होंने घोषणा की कि इस अवसर पर वे जे-रिनपोछे के 'प्रतीत्य समुत्पाद की स्तुति' पर प्रवचन देना पसंद करेंगे।

परम पावन ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए कहा कि वे भी बुद्ध के प्रति महान कृतज्ञता और भक्ति का भाव रखते हैं। क्योंकि यह उनकी शिक्षाओं का ही प्रतिफल है कि वह बोधिचित्त के महत्वाकांक्षी चित्त और शून्यता की समझ को विकसित करने में सक्षम हुए हैं।

उन्होंने आगे कहा, 'बचपन में भी मुझमें कही गई बातों को बिना जांचे स्वीकार नहीं करने की प्रवृत्ति थी। मुझे हर कही गई बातों पर सवाल उठाने और इसकी जांच करने की जरूरत महसूस होती थी। दलाई लामा के रूप में मैं पारंपरिक हथियारों का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन मैं बहस कर सकता हूं। और मैं अपनी बुद्धि का उपयोग बुद्ध की शिक्षाओं की जांच करने और दूसरों को समझाने के लिए कर सकता हूं। प्रश्न पूछना और जांच-पड़ताल करना नालंदा परंपरा का मुख्य विषय है।

मुझे खुनु लामा रिगज़िन तेनपा से 'प्रतीत्य समुत्पाद की स्तुति' का पाठ और उसकी व्याख्या मिली है।

परम पावन ने घोषणा की कि 'प्रतीत्य समुत्पाद बुद्ध की शिक्षा को परिभाषित करता है। इसके लिए तिब्बती शब्द 'दस-जंग' है। इनमें से पहले दस का अर्थ आश्रित रहना और दूसरे जंग का मतलब उत्पन्न होने वाला है। इससे हमें वास्तविकता का बोध होता है। सब कुछ आश्रित है। कुछ भी स्वतंत्र नहीं है। चीजें अन्य कारकों पर निर्भरता में उत्पन्न होती हैं। चूंकि कुछ भी स्वतंत्र नहीं है, इसलिए सब कुछ निर्भर संबंधों के माध्यम से आता है।'

उन्होंने घोषणा की, 'हम सभी बुद्ध शाक्यमुनि के अनुयायी हैं और उनकी इस करुणा को चुकाने का सबसे अच्छा तरीका बोधिचित्त के परोपकारी चित्त और शून्यता की समझ को विकसित करना है। मैं यही करता हूं और इस साधना के कारण मैं सहज महसूस करता हूं।'

परम पावन ने अपने साथ तस्वीरें लेने के लिए समूहों में एकत्रित हुए श्रोताओं के कई प्रश्नों के उत्तर भी दिए।

## ◆ परम पावन दलाई लामा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से सहानुभूति व्यक्त की

dalailama.com, जून ०३, २०२३

**धर्मशाला।** आज ०३ जून की सुबह परम पावन दलाई लामा ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने लिखा कि कल शाम बालासोर में हुई दुखद ट्रेन दुर्घटना की खबर देखकर उन्हें बहुत गहरा आघात लगा है। इस दुर्घटना में कई लोगों की जान चली गई और अनेक लोग घायल हुए हैं।

उन्होंने लिखा, 'मैं उन परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने प्रियजनों को खोया है और उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस त्रासदी से घायल हुए हैं और अन्य तरह से प्रभावित हुए हैं।'

राज्य सरकार और केंद्र सरकार सहित अन्य एजेंसियां इस दुखद दुर्घटना से घायलों और अन्य लोगों को चिकित्सा उपचार और सहायता प्रदान करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। इसकी मैं दिल से प्रशंसा करता हूं। ओडिशा के लोगों के साथ एकजुटता के प्रतीक के तौर पर दलाई लामा ट्रस्ट (डीएलटी) चिकित्सा उपचार के साथ-साथ राहत और बचाव के प्रयासों में अपनी ओर से दान दे रहा है।

जैसा कि आप जानते हैं, मुझे कई बार ओडिशा जाने का अवसर मिला है और आपसे मिलने का सम्मान भी मिला है, पिछली बार हम २०१७ में मिले थे।

परम पावन ने प्रार्थना और शुभकामनाओं के साथ अपने पत्र को समाप्त किया।

## ◆ सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने ऑस्ट्रेलिया के नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित किया

tibet.net

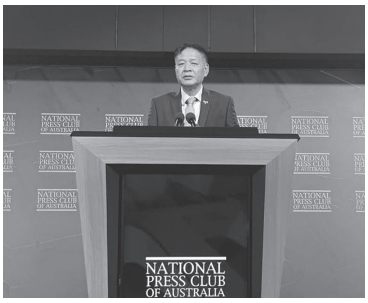


**२० जून, २०२३ कैनबरा।** सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने आज २१ जून २०२३ को 'चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने और क्षेत्र में शांति हासिल करने' के मुद्दे पर ऑस्ट्रेलियाई नेशनल प्रेस क्लब को संबोधित किया।

घंटे भर की बातचीत के दौरान सिक्योंग ने तिब्बत के अंदर चीनी सरकार के दमन, ग्रिड-लॉक सिस्टम, लामाओं के पुनर्जन्म को मान्यता देने के लिए खुद को अधिकृत करने वाले चीनी सरकार के ऑर्डर नंबर- ५, मठों में निगरानी, और तिब्बत के लोगों की तिब्बत के बाहर- अंदर की भी आवाजाही को प्रतिबंधित कर तिब्बत को जेल जैसा बना देनेवाली चीनी सरकार की नीतियों पर चर्चा की। उन्होंने तिब्बत की ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र स्थिति पर भी प्रकाश डाला और अंतरराष्ट्रीय सरकारों से आग्रह किया कि वे तिब्बत के इतिहास की उचित जानकारी के बिना चीनी सरकार की 'तिब्बत चीन का हिस्सा है' जैसे बयानों को न दोहराएं।

मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के माध्यम से चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की प्रतिबद्धता का आश्वासन देते हुए उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक रूप से तिब्बत स्वतंत्र था। सीटीए स्कॉटलैंड की

तरह तिब्बतियों के लिए वास्तविक स्वायत्तता चाहता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक तिब्बत की ऐतिहासिक स्वतंत्र स्थिति को मान्यता नहीं दी जाती, तब तक चीन का हमसे बात करने का क्या उद्देश्य हो सकता है।'

सिक्योंग ने बताया कि परम पावन दलाई लामा के उत्तराधिकार मामलों में चीनी सरकार का हस्तक्षेप पूरी तरह से १५वें दलाई लामा को नियंत्रित करने और प्रभावित करने की एक रणनीति है। ऐसा करके वह आगामी दलाई लामा के माध्यम से तिब्बती लोगों और बौद्ध देशों को नियंत्रित करना चाहता है। हालांकि, उन्होंने एक उदाहरण के तौर पर चीन द्वारा नियुक्त पंचेन लामा का उल्लेख किया कि कैसे चीन अपने पंचेन लामा को तिब्बतियों के बीच वैधता दिलाने में विफल रहा है।

उन्होंने स्कॉटलैंड और साउथ टायरॉल का उदाहरण देते हुए प्रेस क्लब के सदस्यों से सवाल भी पूछे और बताया कि स्वायत्तता से उनका क्या मतलब है। उन्होंने बताया कि यदि तिब्बतियों को इस प्रकार की स्वायत्तता दी जाती है तो वे पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संविधान के ढांचे के तहत रहने में प्रसन्न होंगे। उन्होंने कहा, 'बात यह नहीं है कि कौन शासन करता है, बात यह है कि शासन की गुणवत्ता कैसी है।'

ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के एंड्रयू टिलेट ने सवाल पूछा कि क्या अंतरराष्ट्रीय मीडिया में तिब्बत मुद्दे की लोकप्रियता कम हो गई है। सिक्योंग ने जवाब दिया कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध को हिंसक संघर्षों की तुलना में कम मीडिया कवरेज मिलता है और कहा कि हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। उन्होंने आगे सूचना प्रवाह पर प्रतिबंध के बारे में बात की और बताया कि तिब्बत पर समाचारों की कमी का मतलब यह नहीं है कि तिब्बत के अंदर समस्याओं की कमी हो गई है।

एबीसी के स्टीफ़न डेज़िडज़िक ने सिक्योंग से चीन के साथ सीमा संघर्ष के बाद तिब्बत मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण में बदलाव के बारे में पूछा। सिक्योंग ने कहा कि चीन के साथ सीमा पर झड़पों के मद्देनजर भारत अपने लिए खड़ा है और कहा कि केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का भारत सरकार के साथ बहुत पारदर्शी संबंध है। ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ ऑकस और क्वाड जैसे नए गठबंधनों के गठन के साथ भारत यह कहते हुए और अधिक मजबूत रुख अपना रहा है कि यदि सभी क्षेत्रों से सैनिक नहीं हटेंगे तो संबंध सामान्य नहीं होंगे। मैं वास्तव में भारत की मजबूत स्थिति की सराहना करता हूं।

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के मैथ्यू नॉट ने सिक्योंग से पूछा कि क्या मानवाधिकारों के हनन के दोषी चीन पर प्रतिबंध लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया का आह्वान करना दोनों व्यापारिक साझेदारों के बीच द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक नहीं होगा? इस पर सिक्योंग ने उत्तर दिया कि ऑस्ट्रेलियाई सरकार को सभी देशों के प्रति एक समान नीति रखनी चाहिए और छोटे देशों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, जहां ऐसा करना अधिक सुविधाजनक है। जबकि चीन जैसे बड़े देश सब कुछ करके बच निकलते हैं।

एसबीएस से पाब्लो विनालेस ने सिक्योंग से पूछा कि क्या चीन और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों में ठहराव तिब्बत मुद्दे की कीमत पर आया है? सिक्योंग ने इसका जवाब देते हुए कहा कि जब बात चीन की आती है तो वह इससे जुड़ी संवेदनशीलता को समझते हैं, खासकर जब यह राष्ट्रीय हितों से जुड़ा हो। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में चीन की सक्रियता के कारण ही ऑस्ट्रेलिया ऑकस और क्वाड का हिस्सा बना है और ऑस्ट्रेलिया को भी खुद को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इसलिए, उन्होंने चीन को सही दिशा में ले जाने के लिए साझेदारों के साथ रणनीतिक रूप से काम करने का सुझाव दिया।

सिक्योंग ने तिब्बती प्रतिनिधियों और चीनी अधिकारियों के बीच पिछली वार्ता और भविष्य की वार्ता के दृष्टिकोण पर सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने बताया कि परदे के पीछे चर्चाएं हो रही थीं, लेकिन मामले की संवेदनशीलता के कारण वह इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते।

सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड और द एज के मुख्य राजनीतिक संवाददाता और प्रेस गैलरी, एनपीसी के पूर्व अध्यक्ष डेविड क्रो ने इस कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम से पहले सिक्योंग ने एनपीसी के अध्यक्ष टिम शॉ और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मौरिस रीली से भी मुलाकात की।

इससे पहले आज सुबह, सिक्योंग ने ऑस्ट्रेलियाई रणनीतिक नीति संस्थान का दौरा किया, जहां उन्होंने तिब्बत के भू-राजनीतिक महत्व और तिब्बत के अंदर मौजूदा स्थितियों से संबंधित विषयों पर बात की। एएसपीआई कैनबरा स्थित एक स्वतंत्र और निष्पक्ष थिंक टैंक है, जिसका रणनीतिक नीति और रक्षा पर विशेष ध्यान है।

एएसपीआई के कार्यकारी निदेशक जस्टिन बस्सी ने सिक्योंग और प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया और आगे जुड़ाव और ज्ञान साझा करने में वृद्धि की उम्मीद जताई।

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) की मुख्य चिंताओं से संवाददाताओं को अवगत कराया और फिर भारत-तिब्बत सीमा विवादों और चीन द्वारा तिब्बत में तिब्बतियों की समस्यामूलक डीएनए प्रोफाइलिंग से संबंधित विषयों पर अधिक विस्तृत चर्चा जारी रखी। एएसपीआई के विषय विशेषज्ञों ने भी व्यापक विषयों पर सिक्योंग से प्रश्न पूछने का अवसर लिया। सिक्योंग ने तिब्बती परिप्रेक्ष्य और ज्ञान के बारे में जानकारियां प्रदान कीं। सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने एएसपीआई के महत्वपूर्ण कार्यों को स्वीकार करते हुए बैठक का समापन किया, और समान लक्ष्यों के लिए काम कर रहे ऑकस (ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी) और क्वाड (ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच राजनयिक साझेदारी) जैसी चल रहे बहुपक्षीय गठबंधनों को लेकर अपनी आशावादी दृष्टिकोण को व्यक्त किया। साथ ही एएसपीआई और सीटीए के बीच आगे संबंध बनाने और सामूहिक रूप से काम करने की उम्मीद जताई।

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने ऑस्ट्रेलियाई राजधानी कैनबरा में सांसद शाइनी न्यूमैन, सीनेटर डीन स्मिथ, तिब्बत के लिए ऑस्ट्रेलियाई सर्वदलीय संसदीय समूह के सह-अध्यक्ष सांसद ल्यूक गोसलिंग और सांसद सुसान टेम्पलमैन के साथ ऑस्ट्रेलियाई संसद में दोपहर की बैठक के साथ आधिकारिक कार्यक्रम को संपन्न किया। सिक्योंग आज शाम ऑस्ट्रेलियाई शहर मेलबर्न के लिए रवाना हो गए।

## ◆सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने अपनी पहली यात्रा के समापन से पहले न्यूजीलैंड के सांसदों से मुलाकात की

tibet.net, जून १६, २०२३

**वेलिंगटन।** सिक्योंग पेन्पा छेरिंग न्यूज़ीलैंड में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के अंतिम दिन शुक्रवार, १६ जून को वेलिंगटन में न्यूज़ीलैंड के

नेशनल लाइब्रेरी में फ्रेंड्स ऑफ़ तिब्बत, निंगजे चैरिटेबल ट्रस्ट और धर्म के छात्रों से मिले। उन्होंने तिब्बत मुद्दे, तिब्बती पहचान, तिब्बत के पर्यावरण, और तिब्बती धर्म और संस्कृति के महत्व को खत्म करने के उद्देश्य से लागू की जा रहीं चीनी सरकार की नीतियों के तहत तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति पर सभा को संबोधित किया। सिक्योंग ने तिब्बती आंदोलन को लंबे समय से समर्थन देने के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया।

दोपहर में सिक्योंग ने वेलिंगटन में संसद का दौरा किया। इस यात्रा में न्यूजीलैंड के राष्ट्रीय पार्टी के विदेशी मामलों के प्रवक्ता और चीन पर अंतर-संसदीय गठबंधन के सह-अध्यक्ष सांसद साइमन ओ'कॉनर द्वारा आयोजित लंच बैठक भी शामिल थी, जिसमें विभिन्न राजनीतिक समूहों के सांसदों ने हिस्सा लिया।

बैठक में एसीटी राजनीतिक दल के सांसद जेम्स मैकडोवाल और लेबर पार्टी के सांसद हेलेन व्हाइट के साथ ग्रीन पार्टी के सांसद गोलरिज घरामन शामिल हुए। बैठक के दौरान सिक्योंग ने तिब्बत के अंदर वर्तमान गंभीर स्थिति, तिब्बती पहचान को नष्ट करने के लिए चीनी सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी उपायों, तिब्बती धर्म और संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के महत्व को उठाया। उन्होंने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री से तिब्बत का मुद्दा उठाने का आग्रह करने पर भी जोर दिया।

सिक्योंग के साथ ओओटी कैनबरा के प्रतिनिधि कर्मा सिंगे भी थे।

इस यात्रा में संसद का एक संक्षिप्त दौरा भी शामिल रहा। सिक्योंग कल यानि १७ जून की भोर में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे।

## ◆ सिक्योंग ने सिडनी में आधिकारिक कार्यक्रमों के दौरान तिब्बत के अंदर की स्थिति पर प्रकाश डाला

tibet.net, जून १९, २०२३

**सिडनी।** केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने १८ जून २०२३ को सिडनी में और उसके आसपास रह रहे तिब्बती युवाओं और वॉलंटरी तिब्बत एडवोकेसी ग्रुप (वी-टीएजी) के सदस्यों के साथ सभा कर उनसे बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के दूसरे दिन की शुरुआत की। उन्होंने सभा को तिब्बत के इतिहास, तिब्बती पठार के उद्भव और तिब्बत के अंदर की वर्तमान गंभीर स्थिति के बारे में अवगत कराया। सिक्योंग ने तिब्बती युवाओं को सलाह दी कि वे तिब्बत पर अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़कर तिब्बती इतिहास के बारे में जानें और इसपर ध्यान दें। इसके साथ ही वे तिब्बत समर्थन आंदोलन में भाग लें। इसके बाद उन्होंने प्रश्नोत्तर सत्र में श्रोताओं के प्रश्नो के उत्तर दिए।

सिक्योंग पेनपा छेरिंग की ऑस्ट्रेलिया की आधिकारिक यात्रा के सम्मान में ऑस्ट्रेलियाई सांसद डॉ सोफी स्कैम्प्स ने १८ जून २०२३ को न्यू पोर्ट, सिडनी में रॉयल मोटर यॉच क्लब में दोपहर के विशेष भोजन का आयोजन किया। सिक्योंग ने इस कार्यक्रम में भाग लेनेवाले तिब्बत के स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों और समर्थकों के साथ भी अलग से बातचीत की। ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने इस साल अप्रैल में अपनी धर्मशाला यात्रा के दौरान परम पावन दलाई लामा से मिलने को याद कर प्रसन्नता व्यक्त की और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व और सरकारी संगठनों और गैर सरकारी संगठनों के दौरे के अपने अनुभव को भी साझा किया। सिक्योंग ने आयोजन की मेजबानी के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया और तिब्बत के अंदर की स्थिति, तिब्बत के पर्यावरण की रक्षा के महत्व, तिब्बती पठार के उद्भव और पड़ोसी देशों के लिए तिब्बत की नदियों के महत्व पर प्रकाश डाला।

बाद में दोपहर में यूटीएस के एशिया-प्रशांत अनुसंधान समूह और सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान विभाग द्वारा आयोजित प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सिडनी (यूटीएस) में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने 'चीन-तिब्बत संघर्ष का स्थायी और टिकाऊ समाधान विश्व शांति के लिए अनिवार्य है' विषय पर अपनी बात रखी। कार्यक्रम के दौरान लोकतंत्र समर्थक, विशेषज्ञ, लेखक और सिडनी स्थित चीन-तिब्बत मैत्री संघ के सदस्य उपस्थित थे। सिक्योंग ने उन्हें तिब्बत की ऐतिहासिक रूप से स्वतंत्र स्थिति, चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए मध्यम मार्ग दृष्टिकोण अपनाने और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की गतिविधियों से अवगत कराया।

## ◆ सिडनी में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग का आधिकारिक कार्यक्रम संपन्न

tibet.net, २० जून, २०२३

**सिडनी।** सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने सिडनी प्रवास के अंतिम दिन १९ जून २०२३ को सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के पत्रकार मैथ्यू नॉट को साक्षात्कार देने के साथ अपने आधिकारिक कार्यक्रमों की शुरुआत की।

दोपहर बाद उन्होंने न्यू साउथ वेल्स राज्य की संसद में 'निर्वासन, लचीलापन और निर्वासन में लोकतंत्र' विषय पर अपना संबोधन दिया। उन्होंने सभा को परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म प्रक्रिया में चीनी सरकार के हस्तक्षेप, मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के माध्यम से चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के प्रति सीटीए की प्रतिबद्धता, तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति से अवगत कराया और परम पावन दलाई लामा के प्रति आभार व्यक्त किया।

इस कार्यक्रम की सह-मेजबानी राज्य संसद के सदस्य माइकल रेगन और जेम्स ग्रिफिन ने तिब्बत सूचना कार्यालय और ऑस्ट्रेलिया तिब्बत परिषद के समन्वय में की। इस कार्यक्रम का संचालन ऑस्ट्रेलियाई प्रस्तोता और एसबीएस न्यूज़ के पत्रकार कार्ला ग्रांट ने किया।

कार्यक्रम के बाद सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा के लिए रवाना हो गए।

सिडनी में आधिकारिक कार्यक्रमों के सफल समापन के बाद सिक्योंग दोपहर में कैनबरा पहुंचे। कैनबरा आगमन पर अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में तिब्बती संघ के सदस्यों, तिब्बत सूचना कार्यालय के पूर्व प्रतिनिधियों और कर्मचारियों, तिब्बत समर्थकों और तिब्बती समुदाय द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।

शाम को सिक्योंग ने १६वें कशाग के दृष्टिकोण के बारे में कैनबरा और उसके आसपास रहनेवाले तिब्बती समुदाय को संबोधित किया। सभा में परम पावन दलाई लामा के प्रति आभार व्यक्त किया गया, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के ढांचे को मजबूत करने, तिब्बती बस्तियों का भरण-पोषण और निर्वासन में आने वाले आवास संबंधी मुद्दों के समाधान को लेकर चर्चाएं की गईं। इसके अलावा, सिक्योंग ने घटती तिब्बती आबादी के बारे में बात की और तिब्बती इतिहास पर ध्यान देने और सीखने, वैश्विक मंच पर तिब्बती मुद्दे की स्थिति को उठाने और अमेरिकी कांग्रेस में नए तिब्बत बिल को फिर से पेश करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

## ◆ ब्रिटिश द्वीपों, नॉर्डिक- बाल्टिक क्षेत्रों और पोलैंड में तिब्बत पर काम कर रहे नागरिक समूह स्वीडन में पहली क्षेत्रीय बैठक करेंगे

tibet.net, १६ जून, २०२३

**लंदन।** लंदन स्थित तिब्बत कार्यालय (ओओटी) स्वीडिश-तिब्बत समिति और स्वीडन के तिब्बती समुदाय के साथ मिलकर स्टॉकहोम में १८ से २० जून २०२३ तक तीन दिवसीय बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें तिब्बत मुद्दे का समर्थन करने वाले सभी स्थानीय नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) को आमंत्रित किया गया है।

ओओटी-लंदन अपनी पहुंच वाले क्षेत्र में छह तिब्बती सामुदायिक संगठनों और ग्यारह स्थानीय तिब्बत समर्थक समूहों के साथ नियमित कार्य करता है। इसके पहुंच वाले क्षेत्रों में ब्रिटिश द्वीपों, नॉर्डिक- बाल्टिक क्षेत्रों और पोलैंड के ११ देश शामिल हैं। कार्यालय को स्थानीय सीएसओ के साथ साझा की गई घनिष्ठ साझेदारी और इन सीएसओ की उपलब्धियों पर गर्व है, इस तथ्य के बावजूद कि उनमें से अधिकांश को सीमित संसाधनों वाले कुछ समर्पित स्वयंसेवकों द्वारा दशकों से चलाया जा रहा है।

बैठक में २५ प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य स्थानीय आवाजों को एक मंच प्रदान करना है और स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से हितधारक समूहों के बीच भविष्य के सहयोग के लिए स्थानीय और देश के बाहर संबंधों को मजबूत करना और संभावित रूप से एक समन्वित क्षेत्रीय आवाज तैयार करना है जो पूरे यूरोप और दुनिया भर में तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को बढ़ा सके। बैठक के पहले और दूसरे दिन मुख्य रूप से तिब्बत को लेकर एडवोकेसी हुई। इसका समापन १९ की शाम को स्वीडिश संसद में तिब्बत कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। तीसरा दिन ओओटी लंदन के क्षेत्र में तिब्बती समुदाय समूहों की क्षमता निर्माण पर केंद्रित होगा।

ब्रसेल्स और जिनेवा स्थित सहयोगी तिब्बत कार्यालय क्रमशः यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र संस्थानों में अपनी विशेषज्ञता के साथ तिब्बत के पक्ष में बातों को रखेंगे और अपने क्षेत्राधिकार में आनेवाले अन्य यूरोपीय देशों में तिब्बती अनुभवों का प्रचार कर ओओटी का सहयोग करेंगे। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग ने इस बैठक में भाग लेने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया है।

स्वीडन को यूरोपीय संघ की परिषद की वर्तमान अध्यक्षता के कारण इस बैठक की मेजबानी के लिए चुना गया था, और अक्तूबर २०२२ से नई स्वीडिश सरकार और यूरोपीय संसद के प्रारंभिक संपर्कों के दौरान पहले से इस मुद्दे पर रुचि को देखते हुए इसे आगे और निर्माण करने के लिए चुना गया था। वर्तमान स्वीडिश संसद में सांसद मार्गरेटा सीडरफेल्ट की अध्यक्षता में तिब्बत मैत्री समूह में सांसदों की मजबूत सदस्यता है। मार्गरेटा इस वर्ष के अंत में धर्मशाला आनेवाले स्वीडिश सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भी करेंगी। स्थानीय स्तर पर तिब्बत से संबंधित संगठनों के मजबूत सहयोग ने इसमें अतिरिक्त लाभ भी प्रदान किया है।

## ◆ भारत-तिब्बत मैत्री संघ की सिरमौर इकाई के सदस्यों से मिलीं कलोन नोरजिन डोल्मा

tibet.net, १६ जून, २०२३

**धर्मशाला।** भारत-तिब्बत मैत्री संघ की सिरमौर इकाई के सदस्य परम पावन दलाई लामा का दर्शन करने और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और उसके कामकाज को देखने के लिए धर्मशाला की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।

आज सुबह एडवोकेट अनिंदर सिंह नॉटी (व्यापार मंडल, पांवटा साहिब के अध्यक्ष) और नरिंदर पाल सिंह (द स्कॉलर होम्स स्कूल, पांवटा साहिब के निदेशक) के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग की कलोन (मंत्री) नोरजिन डोल्मा और विभाग के सचिव कर्मा चोयिंग से मुलाकात की। एक घंटे की बातचीत के दौरान कलोन नोरज़िन ने उन्हें सीटीए के संगठनात्मक ढांचे और कार्यों और इसके अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दोहरे उद्देश्यों या वर्तमान प्रशासन के प्राथमिक कार्य पर प्रकाश डाला जो लंबे समय से चले आ रहे चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने और निर्वासन में तिब्बतियों के कल्याण का ध्यान रखने को लेकर निश्चित किया गया है।

कलोन ने चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने में सीटीए के मौलिक राजनीतिक रुख के तौर पर मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के बारे में बात की। सभा तिब्बत के अंदर मौजूदा स्थिति से भी परिचित थी, जिसमें सीसीपी द्वारा हाल ही में लागू की गई कठोर नीतियां शामिल हैं। इनमें पांच साल से अधिक उम्र के तिब्बतियों का बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह और तिब्बती बच्चों को जबरन विलय करने और सांस्कृतिक रूप से उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए डिज़ाइन किए गए औपनिवेशिक

बोर्डिंग स्कूलों के विशाल नेटवर्क में भर्ती करना शामिल है।

कलोन ने आगे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए तिब्बत मुद्दे के महत्व और तिब्बत समर्थक समूहों के प्रयासों और एडवोकेसी (पक्षधरता) के माध्यम से तिब्बत द्वारा प्राप्त वैश्विक समर्थन के बारे में बात की। प्राचीन काल से तिब्बत के भारत के साथ गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर जोर देते हुए कलोन ने भारत सरकार और भारत के लोगों को उनकी निरंतर करुणा और उदारता के लिए धन्यवाद दिया।

सचिव कर्मा चोयिंग ने पूरे भारत में विभिन्न तिब्बत समर्थक समूहों के साथ समन्वय के माध्यम से तिब्बत की स्वतंत्रता के संघर्ष में भारत- तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) की अपरिहार्य भूमिका के बारे में सभा को समझाया। उन्होंने सिरमौर से आने वाले भारत-तिब्बत मैत्री संघ के सदस्यों से भविष्य की पहल और कार्यक्रमों के लिए आईटीसीओ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का आग्रह किया।

बातचीत के बाद अतिथि प्रतिनिधिमंडल को तिब्बत संग्रहालय और तिब्बत टीवी प्रसारण स्टूडियो के दौरे पर ले जाया गया। इस दौरे में सिरमौर जिले के सेटलमेंट अधिकारियों- पोंटा बस्ती के टीएसओ गेलेक जयंग, पुरुवाला बस्ती के टीएसओ तेनजिन नामग्याल, कामराव बस्ती के टीएसओ रैप्टन छेरिंग और सतौन बस्ती के टीएसओ सोनम वांगड्यू ने काफी मदद की।

## ◆ तिब्बती नेताओं ने नई दिल्ली में विश्व के शीर्ष राजनयिकों से मुलाकात की

tibet.net, ०७ जून, २०२३

**नई दिल्ली।** निर्वासित तिब्बत सरकार के केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की कशाग (कैबिनेट) और संसद की तीन दिवसीय संयुक्त राजनयिक आउटरीच पहल के तहत यहां कम से कम १७ देशों के राजदूतों या उप राजदूतों के साथ अनेक बैठकें आयोजित की गईं, जिनमें अमेरिका, चेक गणराज्य, लिथुआनिया और ताइवान देश शामिल हैं।

तिब्बती प्रतिनिधिमंडल में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग, अध्यक्ष खेनपो सोनम तेनफेल, कलोन नोरज़िन डोल्मा (मंत्री) और निर्वासन में तिब्बती संसद की स्थायी समिति के सदस्य शामिल थे। तिब्बती प्रतिनिधिमंडल में सांसद तेनपा यारफेल, सांसद खेनपो कड़ा न्गोडुप सोनम, सांसद गेशे ल्हारम्पा गोवो लोबसांग फेंडे, सांसद दोरजी छेतेन, सांसद छेरिंग ल्हामो, सांसद गेशे अटोंग रिनचेन ग्यालछेन, सांसद छेरिंग यांगचेन, सांसद फुरपा दोरजी ग्यालधोंग और सांसद लोबसांग थुप्टेन के साथ सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव कर्मा चोयिंग भी शामिल थे।

इस पहल के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिकी, यूरोपीय, एशियाई और अन्य देशों समेत करीब १७ देशों के वरिष्ठ राजनयिकों से मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को तीन समूहों में विभाजित किया गया था। इनमें से हरेक का नेतृत्व सिक्योंग पेन्पा छेरिंग, अध्यक्ष खेनपो सोनम तेनफेल और सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग के कलोन नोरज़िन डोल्मा कर रही थीं।

बैठकों के दौरान प्रेस को संबोधित करते हुए अध्यक्ष खेनपो सोनम तेनफेल ने कहा, 'सीटीए की यह संयुक्त पक्षधरता पहल दुनिया की प्रमुख शक्तियों के शीर्ष राजनयिकों के साथ जुड़ने और तिब्बत मुद्दे के लिए समर्थन हासिल करने में बेहद सफल रही है।'

इसके अतिरिक्त प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय संसद और भारतीय राजनीतिक दलों के मुख्यालयों का दौरा किया। उन्होंने तिब्बत और तिब्बती लोगों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारतीय सांसदों से भी मुलाकात की।

## ◆ चेक सीनेट समिति में तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप रोकने और तिब्बतियों का जबरन विलय रोकने के लिए चीन से आह्वान वाला प्रस्ताव पारित

tibet.net, ०१ जून, २०२३

**जेनेवा।** चेक गणराज्य की सीनेट ने तिब्बती बच्चों को जबरन आत्मसात करने और तिब्बत में चीन द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता में लगातार हस्तक्षेप पर अपनी 'गहरी चिंता' व्यक्त करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। यह प्रस्ताव ३० मई २०२३ को सीनेट की शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, मानवाधिकार और याचिकाओं संबंधी समिति द्वारा स्वीकृत किया गया था।

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों के निष्कर्षों पर आधारित प्रस्ताव में तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से सुनियोजित तरीके से अलग करने और अनिवार्य औपनिवेशिक आवासीय विद्यालयों को लेकर 'गहरी चिंता' की अनुगूंज सुनाई पड़ती है। पारित संकल्प में चीन को जबरन आवासीय विद्यालयों की अनिवार्यता को ख़त्म करने और तिब्बती बच्चों को तिब्बती भाषा में शिक्षित करने की अनुमति देने और तिब्बती संस्कृति और परंपराओं से उन्हें जुड़ने देने की अनुमति देने का आह्वान किया गया है।

संकल्प ने परम पावन १४वें दलाई लामा के पुनर्जन्म सहित पुनर्जन्म की सदियों पुरानी तिब्बती बौद्ध रिवाजों में दखल देने वाली चीनी सरकार की नीतियों पर अपनी कड़ी आपत्ति जताई है। इसके अलावा, समिति ने घोषणा की कि पुनर्जन्म की पारंपरिक तिब्बती बौद्ध धार्मिक प्रथा पर चीनी सरकार का प्रभाव और हस्तक्षेप तिब्बती लोगों की धर्म और विश्वास की स्वतंत्रता का 'गंभीर' उल्लंघन माना जाएगा।

सीनेट समिति द्वारा व्यक्त की गई उपरोक्त चिंताओं के मद्देनजर चेक गणराज्य की सरकार से चीन के साथ अपने द्विपक्षीय और बहुपक्षीय संपर्कों में तिब्बत में बिगड़ती स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करने और चीन से आवासीय विद्यालयों को 'तुरंत बंद' करने का आह्वान करने की सिफारिश की गई है। इसमें कहा गया है कि चीन को तिब्बत और धार्मिक प्रमुखों के पुनर्जन्म की तिब्बती बौद्ध धार्मिक परंपरा का सम्मान करना चाहिए। इसके अलावा, सीनेट समिति ने समिति के अध्यक्ष को अपनाए गए प्रस्ताव को सीनेट के अध्यक्ष, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री और चेक गणराज्य के विदेश मामलों के मंत्री को प्रेषित करने का आग्रह किया गया है।

तिब्बत ब्यूरो-जिनेवा के प्रतिनिधि थिनले चुक्की ने सीनेटरों के साथ अपनी पिछली बैठक के दौरान चर्चा में उठाए गए मुद्दों को लेकर संकल्प पारित करने के लिए समिति, विशेष रूप से समिति के उपाध्यक्ष और तिब्बत के लिए चेक सीनेट संसदीय समूह के अध्यक्ष माननीय प्रेमिसल रबास को धन्यवाद दिया। संकल्प में फिर से चेक गणराज्य की मजबूत एकजुटता और तिब्बती लोगों की प्रतिज्ञा के समर्थन का आश्वासन दिया गया है। प्रतिनिधि थिनले ने टिपण्णी की, 'हमें आशा है कि यह संकल्प इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चेक संसद में ठोस संसदीय प्रस्तावों को आगे बढ़ाएगा।'

## ◆ धर्मशाला के दो दिवसीय दौरे पर आए उच्चस्तरीय यूएसएड प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व से मुलाकात की

tibet.net, १३ जून, २०२३

**धर्मशाला।** १३-१४ जून २०२३ को धर्मशाला के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे पर आए उच्चस्तरीय यूएसएड प्रतिनिधियों ने आज केंद्रीय तिब्बती प्रशासन का दौरा किया और तिब्बती संसद के अध्यक्ष खेनपो सोनम तेनफेल, सिक्योंग पेन्पा छेरिंग, शिक्षा विभाग के कलोन (मंत्री) थरलाम डोल्मा और सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग (डीआईआईआर) के कलोन (मंत्री) नोरजिन डोल्मा से आज सुबह कशाग सचिवालय में मुलाकात की।

डीआईआईआर सचिव कर्मा चोयिंग और प्रोटोकॉल अधिकारी तेनज़िन पलजोर ने आज कांगड़ा हवाई अड्डे पर दस सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया।

सिक्योंग के साथ शिष्टाचार मुलाकात के बाद प्रतिनिधिमंडल ने तिब्बत संग्रहालय और तिब्बती वर्क्स एंड आर्काइव्स (एलटीडब्ल्यूए) के पुस्तकालय का दौरा किया।

इसके बाद दोपहर में उन्होंने धर्मशाला स्थित केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और तिब्बती एनजीओ के प्रतिनिधियों के साथ एक गोलमेज बैठक की।

पॉलिसी एंड प्रोग्रामिंग के उप प्रशासक इसोबेल कोलमैन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल में एशिया ब्यूरो के सहायक प्रशासक माइकल शिफर, मिशन के उप निदेशक करेन क्लिमोव्स्की, स्टॉफ फॉर पॉलिसी के उप प्रमुख सोनाली कोर्डे, वरिष्ठ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सोफिया ललानी, विशेष सहायक एमिली ग्रीन, कंट्रोल ऑफिसर (इंडिया) इलेन ली, डिप्टी कंट्रोल ऑफिसर (धर्मशाला) बलका डे, कम्युनिकेशन लीड मार्था वैन लिशआउट और जेंडर एडवाइजर ऋतिका चोपड़ा शामिल थी।

## ◆ भारत-तिब्बत मैत्री संघ की सिरमौर इकाई के सदस्यों से मिलीं कलोन नोरजिन डोल्मा

tibet.net, १६ जून, २०२३

**धर्मशाला।** भारत-तिब्बत मैत्री संघ की सिरमौर इकाई के सदस्य परम पावन दलाई लामा का दर्शन करने और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन और उसके कामकाज को देखने के लिए धर्मशाला की दो दिवसीय यात्रा पर हैं।

आज सुबह एडवोकेट अनिंदर सिंह नॉटी (व्यापार मंडल, पांवटा साहिब के अध्यक्ष) और नरिंदर पाल सिंह (द स्कॉलर होम्स स्कूल, पांवटा साहिब के निदेशक) के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग की कलोन (मंत्री) नोरजिन डोल्मा और विभाग के सचिव कर्मा चोयिंग से मुलाकात की। एक घंटे की बातचीत के दौरान कलोन नोरज़िन ने उन्हें सीटीए के संगठनात्मक ढांचे और कार्यों और इसके अधिकार क्षेत्र के तहत विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने दोहरे उद्देश्यों या वर्तमान प्रशासन के प्राथमिक कार्य पर प्रकाश डाला जो लंबे समय से चले आ रहे चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने और निर्वासन में तिब्बतियों के कल्याण का ध्यान रखने को लेकर निश्चित किया गया है।

कलोन ने चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने में सीटीए के मौलिक राजनीतिक रुख के तौर पर मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के बारे में बात की। सभा तिब्बत के अंदर मौजूदा स्थिति से भी परिचित थी, जिसमें सीसीपी द्वारा हाल ही में लागू की गई कठोर नीतियां शामिल हैं। इनमें पांच साल से अधिक उम्र के तिब्बतियों का बड़े पैमाने पर डीएनए संग्रह और तिब्बती बच्चों को जबरन विलय करने और सांस्कृतिक रूप से उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए डिज़ाइन किए गए औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों के विशाल नेटवर्क में भर्ती करना शामिल है।

कलोन ने आगे अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लिए तिब्बत मुद्दे के महत्व और तिब्बत समर्थक समूहों के प्रयासों और एडवोकेसी (पक्षधरता) के माध्यम से तिब्बत द्वारा प्राप्त वैश्विक समर्थन के बारे में बात की। प्राचीन काल से तिब्बत के भारत के साथ गहरे सांस्कृतिक संबंधों पर जोर देते हुए कलोन ने भारत सरकार और भारत के लोगों को उनकी निरंतर करुणा और उदारता के लिए धन्यवाद दिया।

सचिव कर्मा चोयिंग ने पूरे भारत में विभिन्न तिब्बत समर्थक समूहों के साथ समन्वय के माध्यम से तिब्बत की स्वतंत्रता के संघर्ष में भारत- तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ) की अपरिहार्य भूमिका के बारे में सभा को समझाया। उन्होंने सिरमौर से आने वाले भारत-तिब्बत मैत्री संघ के सदस्यों से भविष्य की पहल और कार्यक्रमों के लिए आईटीसीओ के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने का आग्रह किया।
बातचीत के बाद अतिथि प्रतिनिधिमंडल को तिब्बत संग्रहालय और तिब्बत टीवी प्रसारण स्टूडियो के दौरे पर ले जाया गया।

इस दौरे में सिरमौर जिले के सेटलमेंट अधिकारियों- पोंटा बस्ती के टीएसओ गेलेक जयंग, पुरुवाला बस्ती के टीएसओ तेनजिन नामग्याल, कामराव बस्ती के टीएसओ रैप्टन छेरिंग और सतौन बस्ती के टीएसओ सोनम वांगड्यू ने काफी मदद की।

## ◆ प्रतिनिधि डॉ. आर्य ने टोक्यो में तियानमेन नरसंहार की वर्षगांठ में भाग लिया

tibet.net, ०५ जून, २०२३

**टोक्यो।** चीन में लोकतंत्र के लिए प्रतिबद्ध चीनी और जापानी समर्थकों ने ०४ जून २०२३ को टोक्यो के बुक्योकू कुमिन हॉल में तियानमेन चौक नरसंहार की ३४वीं वर्षगांठ मनाई। यह कार्यक्रम तियानमेन त्रासदी के पीड़ितों और दुनिया को यह याद दिलाने के लिए था कि लोकतंत्र के लिए चीनी संघर्ष अब भी जीवित और जारी है।

चाइनीज फेडरेशन फॉर डेमोक्रेसी के अध्यक्ष वांगडाई ने प्रतिभागियों और मीडिया का स्वागत किया। उन्होंने उनकी उपस्थिति के लिए और इस मुद्दे के प्रति रुचि दिखाने के लिए और साथ ही आंदोलन को समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया। वर्षगांठ के समारोह का विषय था 'लेट अस नॉट फॉरगेट द तियानमेन स्क्वायर मस्कर (तियानमेन चौक नरसंहार को न भूलें)'।

चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता और १९८९ के तियानमेन स्क्वायर विरोध के दौरान के छात्र नेता झोउ फेंगसुओ वर्षगांठ समारोह में शामिल होने के लिए अमेरिका से आए थे। उन्होंने तियानमेन त्रासदी पर एक घंटे तक भाषण दिया और बताया कि कैसे चीनी कम्युनिस्ट नेताओं ने क्रूरता से प्रदर्शनकारियों युवाओं का संहार किया। उन्होंने कहा कि वह एक स्वतंत्र देश जापान में आकर खुश हैं, जहां वे स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं और स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए बोल सकते हैं। शी जिनपिंग राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं और वास्तव में अपनी सुरक्षा और कम्युनिस्ट शासन के लिए रक्षा खर्च बढ़ाते हैं। उन्होंने चीन के लोकतंत्रीकरण के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले युवा चीनी छात्रों की आवाज को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए आयोजकों और जापान को धन्यवाद दिया।

परम पावन दलाई लामा के संपर्क कार्यालय के प्रतिनिधि डॉ. आर्य छेवांग ग्यालपो ने इस अवसर पर बोलने का अवसर देने के लिए आयोजकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की खोज और संघर्ष में चीनी लोगों के साथ तिब्बती समुदाय की एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने समझाया कि तिब्बती चीनी विरोधी नहीं हैं, जैसा कि कम्युनिस्ट नेतृत्व द्वारा दुष्प्रचार किया गया है। उन्होंने मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के सार की जानकारी दी और बताया कि कैसे यह दृष्टिकोण चीनी संविधान के ढांचे के अनुकूल है। उन्होंने आगे कहा कि २०१० के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता लियू शियाओबो जैसे लोगों को याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने चीन में लोकतंत्र के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

प्रतिनिधि ग्यालपो के साथ आए तिब्बत हाउस के कर्मचारी छेल्हा ने श्रोताओं को 'तिब्बत नीड्स योर हेल्प (तिब्बत को आपकी सहायता की आवश्यकता है)' पुस्तक की प्रतियां वितरित कीं।

उग्यूर, दक्षिणी मंगोलिया, हांगकांग और फालुन गोंग समुदायों के सदस्यों और प्रतिनिधियों ने सीसीपी शासन की क्रूरता पर बात की और कहा कि सीसीपी नेतृत्व द्वारा मानव अधिकारों, लोकतंत्र और सार्वभौमिक मूल्यों को कम करके आंका जा रहा है और उनका उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से स्वतंत्रता और लोकतंत्र के लिए अपने आंदोलन का समर्थन करने की अपील की और चीन से भूमि और कब्जे वाले क्षेत्रों में अपनी दमनकारी नीति को रोकने का आग्रह किया।

बड़ी संख्या में पत्रकारों ने वर्षगांठ समारोह को कवर किया। जयंती समारोह के अंत में पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया।

चीनी लोकतंत्र आंदोलन के सदस्यों और उनके समर्थकों ने इस दिन की सुबह चीनी दूतावास के सामने विरोध-प्रदर्शन किया। वर्षगांठ के महत्व को उजागर करने और जनता से तियानमेन स्क्वायर त्रासदी को न भूलने की अपील करने के लिए शाम को शिंजुकु पार्क में एक मोमबत्ती सभा भी आयोजित की गई।

## ◆ चीनी संपर्क अधिकारी सुल्ट्रिम ग्यात्सो ने तिब्बती अस्तित्वा के चीनीकरण पर प्रकाश डाला

tibet.net, ०७ जून, २०२३

**लॉस एंजिलिस।** वाशिंगटन स्थित तिब्बत कार्यालय के चीनी संपर्क अधिकारी सुल्ट्रिम ग्यात्सो ने लिबर्टी स्कल्पचर पार्क में तियानमेन नरसंहार की याद में आयोजित एक कार्यक्रम में तिब्बत में लागू बिगड़ती औपनिवेशिक चीनीकरण नीतियों पर प्रकाश डाला, जहां प्रतीक के तौर पर एक महिला की मूर्ति को जंजीरों में बांधकर खड़ा किया गया था। असल में यह एक चीनी महिला थीं, जिन्हें चीन के जियांग्सू प्रांत के शुझोऊ शहर के फेंग काउंटी में एक जर्जर झोपड़ी में वर्षों तक जंजीरों से बांधकर हिरासत में रखा गया था।

सुल्ट्रिम ने औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल और दस लाख से अधिक तिब्बतियों से डीएनए नमूनों के संग्रह के बारे में बात की और परम पावन दलाई लामा की सलाह के अनुसार आंदोलनों में सामान्य आधार खोजने के महत्व को रेखांकित किया।

समारोह में विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों के प्रतिनिधियों और स्थानीय अधिकारियों सहित कई प्रसिद्ध लोकतंत्र समर्थक चीनी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

चेन वीमिंग ने जंजीर वाली महिला की मूर्ति का अनावरण किया, जिसे उन्होंने और उनकी टीम ने निर्माण करवाया था। उन्होंने जंजीर वाली महिला के उदाहरण का हवाला देते हुए मानवाधिकारों के उल्लंघन और चीन में खराब स्थिति पर प्रकाश डाला, हालांकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का दावा है कि तकनीकी

रूप से संचालित समाज में इसकी अर्थव्यवस्था ठीक है। चेन ने फिर जंजीरों से बंधी महिला की जंजीरों को चीन को मुक्त करने की अपनी आशा के प्रतीक के रूप में खोल दिया।

प्रसिद्ध चीनी मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील चेन गुआंगचेंग ने भी सभा में भाषण दिया। उन्होंने भी जंजीर वाली महिला के मामले पर प्रकाश डाला और चीन में मानवाधिकारों के मुद्दों के बारे में अपनी चिंता का इजहार किया। उन्होंने चीन में शांति और स्वतंत्रता लाने के लिए सामूहिक प्रयास करने का आग्रह किया। यू दहाई और चेन चुआंगचुआंग ने भी अपने संगठनों की ओर से बात रखी।

सुल्ट्रिम ०५ जून को प्रो. लाउ होन शियांग से मिलने उनके आवास पर गए। वहां उन्होंने चीनी शाही अभिलेखों पर उनके वर्षों के शोध के लिए प्रशंसा व्यक्त की और किंग और मिंग चीनी रूढ़िवादी इतिहास अभिलेखों में दर्ज तिब्बत की स्थिति के बारे में निष्कर्ष निकाला।

सुल्ट्रिम ग्यात्सो के साथ तिब्बती संसद के पूर्व सदस्य तेनजिंग चोंडेन और दक्षिणी कैलिफोर्निया के तिब्बती एसोसिएशन के अध्यक्ष छेतेन डोलकर फानुचारस भी थे।

## ◆ लद्दाख की कार्यवाहक सीआरओ ने सांसद जामयांग छेरिंग नामग्याल और एडवोकेट ताशी ग्याल्सन से शिष्टाचार भेंट की

tibet.net, १३ जून, २०२३

**लद्दाख।** लद्दाख की कार्यवाहक सीआरओ सोनम चोडन ने लद्दाख से लोकसभा सांसद श्री जामयांग छेरिंग नामग्याल को सीटीए और तिब्बती लोगों की ओर से बधाई देने के लिए आज उनसे शिष्टाचार भेंट की। बैठक के दौरान सीआरओ ने मई में सांसद की सोनमलिंग यात्रा के दौरान तिब्बतियों द्वारा उठाई गई चिंताओं से उन्हें अवगत कराया।

सीआरओ चोडन ने इसके बाद लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी पार्षद एडवोकेट ताशी ग्याल्सन से मुलाकात की। दोनों ने १२ मई को बस्ती की स्थानीय तिब्बती सभा द्वारा आयोजित एक विशेष बैठक के दौरान उठाई गई सोनमलिंग तिब्बती बस्ती द्वारा की गई शिकायतों पर चर्चा की।

कार्यवाहक सीआरओ ने सोनमलिंग में तिब्बतियों को दी जाने वाली सब्सिडी के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, जिसमें ०८ और ०९ शिविरों में ९६ सोलर स्ट्रीट लाइट और एक आंतरिक ब्लैकटॉप रोड प्रदान करना शामिल है। उन्होंने एडवोकेट ताशी ग्याल्सन और ग्रामीण बस्ती में निराश्रित तिब्बती परिवारों के आवासों के जीर्णोद्धार हेतु विकास विभाग के कार्यकारी पार्षद ताशी नामग्याल याकज़ी से भी मुलाकात की।

चर्चा के दौरान सीआरओ ने उनसे लद्दाख में तिब्बती पुनर्वास नीति २०१४ को लागू करने का भी अनुरोध किया और जंगथांग खानाबदोश परिवार के लिए अगलिंग, सराय में एसटीपी और सभी शिविरों के लिए आंतरिक ब्लैकटॉप रोड के मुद्दों को भी उठाया।

## ◆ ऑस्ट्रेलियाई संसद की प्रतिनिधि सभा और सीनेट ने सिक्योंग पेन्पा छेरिंग को सम्मानित किया

tibet.net, २० जून २०२३

**कैनबरा।** ऑस्ट्रेलियाई संसद के दोनों सदनों- प्रतिनिधि सभा और सीनेट- ने २० जून २०२३ को सिक्योंग पेन्पा छेरिंग को सम्मानित किया।

माननीय उपसभापति शेरोन क्लेडन और सदन के सदस्यों की उपस्थिति में सांसद डॉ. सोफी स्कैम्प्स और सांसद सुसान टेम्पलमैन ने ऑस्ट्रेलियाई संसद की कार्यवाही देखने आए सिक्योंग पेन्पा छेरिंग का स्वागत किया।

सांसद सोफी स्कैम्प्स और सांसद सुसान टेम्पलमैन ने सदन का ध्यान चीनी शासन में तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति की ओर दिलाया, जिसमें तिब्बती बच्चों को 'औपनिवेशिक शैली' के बोर्डिंग स्कूलों में जबरन भर्ती करना और परम पावन दलाई लामा के पुनर्जन्म मामले में चीनी सरकार का हस्तक्षेप शामिल है। सांसदों ने तिब्बत मामले में बहुपक्षीय मंचों पर सार्वजनिक और निजी तौर पर सीधे चीन के साथ मानवाधिकारों की वकालत करने के महत्व पर भी जोर दिया।

ऑस्ट्रेलियाई सीनेट में सिक्योंग पेन्पा छेरिंग और उनके साथ आए तिब्बती प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए सीनेटर जेनेट राइस ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से विशेष रूप से एक नीति बनाने और 'चीनी सरकार के किसी भी हस्तक्षेप के बिना दलाई लामा के उत्तराधिकार की रक्षा करने' का आग्रह किया।

सीनेटर राइस ने चीन सरकार से चीन-तिब्बत संघर्ष को हल करने के लिए परम पावन दलाई लामा या उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का भी आह्वान किया।

सीनेटर लिंडा रेनॉल्ड्स ने तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता के गंभीर उल्लंघन और तिब्बती संस्कृति और धर्म के 'जान-बूझकर' चीनीकरण किए जाने के बारे में बढ़ती वैश्विक चिंताओं को उठाया। तिब्बत में सरकार द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों की आलोचना करते हुए सीनेटर रेनॉल्ड्स ने इस नीतियों को 'तिब्बती माता-पिता और बच्चों के अपने परिवारिक इकाइयों की अखंडता को बनाए रखने के उनके अधिकारों में हस्तक्षेप करके उनके अधिकारों का मौलिक उल्लंघन' करना बताया।

सीनेटर डेबोरा ओ'नील ने चीनी सरकार द्वारा तिब्बती धार्मिक अभिव्यक्ति के दमन, अत्यधिक सुरक्षा उपायों, बड़े पैमाने पर निगरानी, यात्रा पर प्रतिबंध और तिब्बती सांस्कृतिक अधिकारों और विरासत पर चीन की दमनकारी नीतियों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की।

सीनेटर लिडिया थोरपे ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार से तिब्बत में सांस्कृतिक संहार के खिलाफ 'खड़े होने' और तिब्बत में चीन द्वारा अपनी संस्कृति थोप कर तिब्बती

संस्कृति को निगल जाने की नीति की संयुक्त राष्ट्र से जांच कराने के लिए सहयोगियों के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समूह बनाने का आह्वान किया।

सीनेटर टोनी शेल्डन ने औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी, तिब्बत में जबरन श्रम और परम पावन दलाई लामा के उत्तराधिकार मामले में चीन के हस्तक्षेप पर भी चिंता व्यक्त की।

सीनेटर जॉर्डन स्टील जॉन और सीनेटर निक मैककिम ने परम पावन १४वें दलाई लामा के उत्तराधिकार के मामले में चीनी सरकार के हस्तक्षेप का कड़ा विरोध करते हुए इस मामले में ऑस्ट्रेलियाई सरकार की निभाने योग्य भूमिका पर प्रकाश डाला।

ऑस्ट्रेलियाई सांसदों और तिब्बत के लिए सर्वदलीय संसदीय समूह के सदस्यों ने धर्मशाला की अपनी हालिया यात्रा के दौरान परम पावन दलाई लामा और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के नेतृत्व से मुलाकात के अपने अनुभवों को व्यक्त किया और तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति अपने निरंतर समर्थन को दोहराया।

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग के साथ कैनबरा स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सिंगे और कैनबरा तिब्बती समुदाय के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

## ◆ कुल मिलाकर शी जिनपिंग एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक भाषा का दृष्टिकोण रखते है

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने शी जिनपिंग के शासन में चीन की तिब्बत नीति पर अपने विचार रखे

tibet.net, २८ जून, २०२३

**दिल्ली।** 'शी जिनपिंग कुल मिलाकर तिब्बत के अंदर अन्य सभी राष्ट्रीयताओं का विलय कर 'एक राष्ट्र, एक संस्कृति और एक भाषा' रखना चाहते हैं। सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने मंगलवार को 'सेंटर फॉर चाइना एनालिसिस एंड स्ट्रैटेजी' द्वारा आयोजित एक सेमिनार में टिप्पणी की- ऐसा कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है जिसे स्वतंत्र दुनिया के लिए खुला छोड़ा गया हो। सिक्योंग ने यहां पर 'शी जिनपिंग के शासन में चीन की तिब्बत नीति' विषय पर एक घंटे तक बात की।

दिल्ली में आयोजित इस एक दिवसीय सम्मेलन में 'तिब्बत में चीन की हालिया गतिविधियां' और 'तिब्बत में धर्म, जातीय और पर्यावरण नीति' विषय पर भी सत्रों का आयोजन किया गया।

निर्वासित तिब्बतियों द्वारा लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए नेता ने परम पावन दलाई लामा द्वारा प्रस्तावित और तिब्बती प्रशासन द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग दृष्टिकोण (एमडब्ल्यूए) की व्याख्या की और स्वतंत्र देश के रूप में तिब्बत की ऐतिहासिक स्थिति की मान्यता को दोहराया, ताकि कुछ लाभ मिल सकें। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एमडब्ल्यूए के माध्यम से चीन-तिब्बत संघर्ष के संभावित समाधान का दक्षिण-पूर्व एशिया में बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस क्षेत्र में तिब्बत की सीमा कई देशों से लगती है।

सिक्योंग पेन्पा छेरिंग ने कहा, 'मुझे लगता है कि आज चीन अपने पास सभी प्रकार की शक्ति होने के बावजूद बहुत असुरक्षित है। चीन एकमात्र ऐसा राष्ट्र है जो किसी भी अन्य राष्ट्र की तुलना में आंतरिक सुरक्षा पर अधिक खर्च करता है और यही कारण है कि वे अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तिब्बत पर अपने अवैध कब्जे को वैधता प्रदान करने के लिए लगातार आग्रह कर रहे हैं। उन्होंने दलील दी कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय चीन-तिब्बत वार्ता का तब तक समर्थन नहीं कर सकता जब तक वे तिब्बत को पीआरसी का हिस्सा होने की बात कहकर इसे वैध ठहराते रहेंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि तिब्बत के इतिहास को अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भावनाओं और कल्पनाओं के आधार पर परिभाषित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि तिब्बत के भविष्या को तय करने की वैधता केवल परम पावन दलाई लामा और तिब्बती लोगों के पास है।

उन्होंने यह भी कहा कि तिब्बत की आधिपत्य (सूजेरिन्टी) की ऐतिहासिक विरासत और भारत के साथ उसके आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को भी चीन बदलने का प्रयास कर रहा है। इसके लिए चीन ने सरकार द्वारा संचालित औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों का विशाल नेटवर्क खड़ा कर लिया है जहां तिब्बती बच्चों को सांस्कृतिक रूप से अज्ञानी बनाकर उन्हें चीनी विचारधारा और प्रचार के द्वारा आत्मसात करने का काम चल रहा है।

सिक्योंग ने कहा कि 'सांस्कृतिक रूप से तिब्बती धीमी मौत मर रहे हैं क्योंकि चीन तिब्बती राष्ट्रीय पहचान की मूल जड़ यानी तिब्बती भाषा पर हमला कर रहा है। चीन तिब्बती भाषा का चीनीकरण करके तिब्बतियों के भावनात्मक समीकरण को बदलने का प्रयास कर रहा है।' उन्होंने तिब्बत के अंदर १५७ लोगों द्वारा किए गए आत्मदाह को इसी तरह के राजनीतिक अभिव्यक्ति पर रोक और अत्यधिक नियंत्रण का प्रत्यक्ष परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि आत्मदाह इस आशा से किया गया था कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय उनकी दुर्दशा पर कुछ ध्यान देगा और परिणामस्वरूप उनके बचाव में आएगा।

चीन हर समय तिब्बत के अंदर अलग-अलग स्तर पर अत्याचार करता रहता है और पत्रकारों, राजनयिकों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को प्रवेश देने से मना करके तिब्बत को अंतरराष्ट्रीय नजरों से ओझल करता रहता है। उन्होंने बताया कि चीन की एकमात्र चिंता कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिरता और अस्तित्व सुनिश्चित करना है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय सीमा पर चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर और ताइवान पर उसकी बार-बार की गई आक्रामकता सीसीपी के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा होने पर उनकी असुरक्षा का ही विस्तार है।

उन्होंने कहा, 'हम वैश्विक समुदाय से चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने में तिब्बत को पीड़ित नहीं, बल्कि एक सहयोगी के रूप में देखने का आग्रह करते हैं । हम सरकारों और नीति निर्माताओं से आग्रह करते हैं कि वे तिब्बत को पीआरसी का हिस्सा कहना बंद करें और इस तरह तिब्बत पर चीन के कब्जे को वैध न बनाएं। सिक्योंग ने अपने समापन भाषण में कहा, अंतरराष्ट्रीय समुदाय और स्वतंत्र दुनिया को अपने मूल्यों के लिए खड़े होने की जरूरत है।

## ◆ कनाडाई सांसदों ने तिब्बत में आवासीय स्कूलों पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया

tibet.net / २३ जून, २०२३

इंटरनेशनल कंपेन फॉर तिब्बत

एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपसमिति में कनाडाई सांसदों ने तिब्बत में अनिवार्य आवासीय विद्यालय प्रणाली के लिए जिम्मेदार चीनी सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की मांग की। इन विद्यालयों के माध्यम से अधिकांश तिब्बती स्कूली बच्चों को उनके परिवारों, भाषा और संस्कृति से अलग कर दिया गया है।

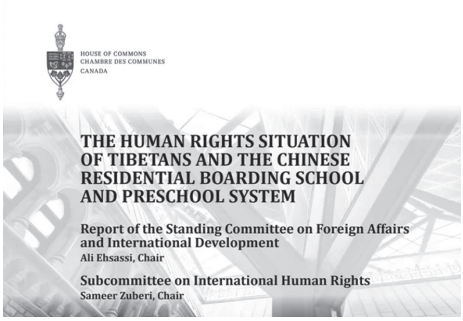


एक नई रिपोर्ट में विदेशी मामलों और अंतरराष्ट्रीय विकास पर स्थायी समिति की अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपसमिति का कहना है कि कनाडाई सरकार को 'तिब्बत में आवासीय बोर्डिंग स्कूल और प्रीस्कूल प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार सरकारी अधिकारियों को मंजूरी देने के लिए विशेष आर्थिक उपाय अधिनियम का उपयोग करना चाहिए।'

रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा को 'तिब्बत आवासीय स्कूलों और अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघनों' के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद और अन्य अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चर्चा में सबसे आगे रखने के लिए सभी पहलों का खुलकर समर्थन करना चाहिए। साथ ही एक बयान भी जारी करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने नवंबर २०२२ में चीनी सरकार को लिखे एक पत्र में आवासीय स्कूलों के बारे में चिंता व्यक्त की थी।

रिपोर्ट के मुताबिक, स्कूलों ने कथित तौर पर लगभग १० लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया है और उन्हें मंदारिन चीनी भाषा सीखने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

इसके परिणामस्वरूप तिब्बती बच्चे अपने माता-पिता और दादा-दादी के साथ संवाद करने और अपनी परंपराओं, इतिहास और तिब्बती पहचान के बारे में जानने की क्षमता खो रहे हैं।

इसका छात्रों और उनके परिवारों पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

रिपोर्ट में कहा गया है, 'स्कूल तिब्बती बच्चों, परिवारों और समुदायों को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसकी हर संभव तरीके से निंदा की जानी चाहिए।'

चीन ने ६० वर्षों से अधिक समय से तिब्बत पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, जिससे यह आज दक्षिण सूडान और सीरिया के साथ पृथ्वी पर सबसे कम स्वतंत्रता वाला देश बन गया है।

## ◆ कनाडा के ओटावा की तीन दिवसीय यात्रा के दौरान वाशिंगटन डीसी स्थित तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि ने कनाडाई सांसदों से मुलाकात की

tibet.net, २० जून, २०२३

**ओटावा।** वाशिंगटन डीसी स्थित तिब्बत कार्यालय ने चीन-तिब्बत संघर्ष को सुलझाने और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन को कार्यक्रम संबंधी सहायता देने का अनुरोध करने के लिए कनाडाई सांसदों और सरकारी अधिकारियों से मिलने के लिए १४-१६ जून तक ओटावा की तीन दिवसीय आधिकारिक यात्रा की। तिब्बत कार्यालय से प्रतिनिधि नामग्याल चोएड्रुप के साथ कनाडा तिब्बत समिति (सीटीसी) के कार्यकारी निदेशक शेराप थेरचिन भी शामिल हुए। कार्यकारी निदेशक ने ओटावा में तीन दिवसीय आधिकारिक कार्यक्रमों का समन्वय किया।

यात्रा के पहले दिन प्रतिनिधि चोएड्रुप को ब्लॉक क्यूबेकॉइस पार्टी के नेता यवेस-फ्रेंकोइस ब्लैंचेट की अध्यक्षता में कॉकस को संबोधित करने का सम्मान मिला। अपने संबोधन में प्रतिनिधि चोएड्रुप ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के दृष्टिकोण और लक्ष्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए तिब्बत की वर्तमान स्थिति पर चर्चा की। कॉकस संबोधन के बाद पार्टी नेता ब्लैंचेट ने विनम्रतापूर्वक एक संसदीय लंच की मेजबानी की, जिसमें सांसद एलेक्सिस ब्रुनेले-डुसेप्पे और सीटीसी निदेशक शेराप थेरचिन शामिल हुए। सांसद ब्रुनेले-डुसेप अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों पर उप-समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। उन्होंने तिब्बतियों के मानवाधिकारों और चीनी आवासीय स्कूल प्रणाली पर उप-समिति की आगामी रिपोर्ट के बारे में जानकारी दी।

ब्लैंचेट ने तिब्बती पहचान के संरक्षण और प्रचार के लिए अटूट समर्थन व्यक्त किया और परम पावन दलाई लामा के प्रति अपना व्यक्तिगत सम्मान व्यक्त किया। लंबे समय से तिब्बत के समर्थक और मित्र, सांसद जूली विग्रोला और सांसद एलेक्सिस ब्रुनेले-डुसेप ने भी चीन-तिब्बती संघर्ष के समाधान के लिए अपना निरंतर समर्थन व्यक्त किया, जिससे ब्लॉक क्यूबेकॉइस पार्टी की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई।

प्रतिनिधि चोएड्रुप ने चीन-तिब्बत वार्ता पर महत्वपूर्ण प्रस्ताव और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन तथा भारत-नेपाल में तिब्बती निर्वासित समुदाय को समर्थन और संस्थागत मजबूती के लिए कनाडा की प्रतिबद्धता के संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए पार्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत के अध्यक्ष सांसद आरिफ विरानी, उपाध्यक्ष सांसद गार्नेट जेनुइस और उपाध्यक्ष जेम्स मैलोनी के साथ बैठकें कीं।

इसके अलावा, प्रतिनिधि चोएड्रुप ने कनाडा के वैश्विक मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की वर्तमान योजनाओं और रणनीतियों पर जानकारी प्रदान की। कवर किए गए विषयों में सीटीए का दृष्टि-पत्र, परम पावन दलाई लामा के उत्तराधिकार से संबंधित मामलों पर ताजा जानकारी के साथ अन्य मुद्दे शामिल थे।

इस यात्रा में पार्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत और ओटावा में तिब्बती समुदाय के सदस्यों के लिए प्रशिक्षु तिब्बती युवाओं के साथ एक बैठक भी शामिल थी। पार्लियामेंटरी फ्रेंड्स ऑफ तिब्बत द्वारा वार्षिक इंटर्नशिप कार्यक्रम के हिस्से के रूप में छह तिब्बती युवा वर्तमान में विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं।

## ◆ तिब्बती मठों की तलाशी के दौरान चीनी अधिकारी भिक्षुओं से दलाई लामा से संबंध त्याग की घोषणा करने को कह रहे हैं

यह कदम उस आदेश के अनुरूप है, जिसके तहत लोकसेवकों को निर्वासित आध्यात्मिक नेता के साथ संबंध तोड़ना आवश्यक तय किया गया है।

rfa.org / संग्याल कुंचोक, २६ जून, २०२३

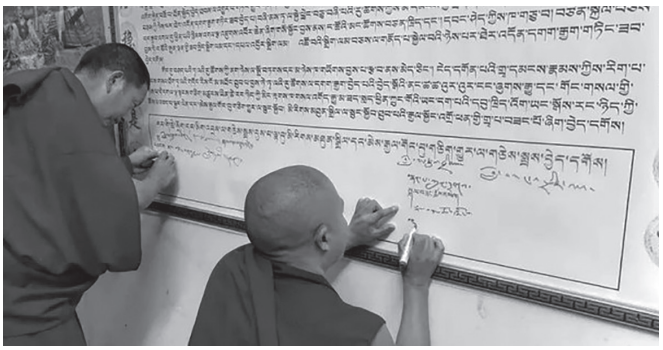

निर्वासन में रह रहे तिब्बती सूत्रों ने रेडियो फ्री एशिया को बताया कि तिब्बत में चीनी अधिकारी बेतरतीब ढंग से मठों की तलाशी ले रहे हैं और भिक्षुओं को तिब्बती बौद्ध धर्म के सबसे प्रमुख आध्यात्मिक नेता 'अलगाववादी' दलाई लामा से सभी संबंध त्यागने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर कर रहे हैं।

दलाई लामा को चीनी नेताओं द्वारा व्यापक रूप से तिब्बत को विभाजित करने के अलगाववादी इरादे के रूप में माना जाता है। तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र था, जिस पर १९५० में बीजिंग ने बलपूर्वक आक्रमण किया और चीन में शामिल कर लिया था।

अब भारत में निर्वासन में रह रहे दलाई लामा केवल इतना कहते हैं कि वह चीन के एक हिस्से के रूप में तिब्बत के लिए अधिक स्वायत्तता चाहते हैं, जिसमें तिब्बत की भाषा, संस्कृति और धर्म की सुरक्षा की गारंटी हो।

आरएफए ने पिछले साल रिपोर्ट दी थी कि चीन ने आधिकारिक सरकारी पदों पर काम करने वाले तिब्बतियों को नौकरी पाने की शर्त के रूप में दलाई लामा से सभी संबंधों को त्यागने की आवश्यकता बताना शुरू कर दिया है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी मठों पर भी इस नियम को लागू कर रहे हैं।

निर्वासन में रह रहे एक तिब्बती ने सुरक्षा कारणों से नाम न छापने का अनुरोध करते हुए आरएफए की तिब्बती सेवा को बताया कि इस महीने की शुरुआत में चीनी अधिकारियों ने सुरक्षा बनाए रखने के आधार पर शेंछा (चीनी भाषा में शेनझा) और सोक (सुओ) काउंटियों में मठों की तलाशी ली।

निर्वासित तिब्बती ने कहा, 'अधिकारी भिक्षुओं के सभी आवासों और मठों के मुख्य मंदिरों की तलाशी ले रहे हैं। शरछा मठ के भिक्षुओं को भी परम पावन दलाई लामा के साथ संबंध त्यागने और दलाई लामा विरोधी समूहों का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया जाता है।'

आरएफए को तिब्बत से प्राप्त एक तस्वीर में शरछा के भिक्षु दीवार पर लगे एक बोर्ड पर हस्ताक्षर करते नजर आ रहे हैं।

बोर्ड पर लिखा गया है कि 'हम दलाई लामा गुट के विरोध में सख्ती से भाग लेंगे और देश (चीन) के प्रति वफादार और समर्पित रहेंगे।'

एक अन्य निर्वासित तिब्बती ने नाम बताने से इनकार करते हुए कहा, 'अपनी तलाशी अभियान में अधिकारी भिक्षुओं की प्रार्थना पांडुलिपियों और पुस्तकों की जांच कर रहे हैं और मंदिरों से प्रार्थना झंडे हटा रहे हैं।'

दूसरे निर्वासित ने कहा, 'उन्होंने इन औचक तलाशी शुरू करने से पहले किसी भी प्रकार की चेतावनी नहीं दी।' इन मठों में भिक्षुओं को एक बैठक के लिए बुलाया गया जहां उन्हें दलाई लामा और अलगाववाद को त्यागने वाले दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया।

## ◆ चीन ने दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो-सोलर प्लांट से विस्थापित तिब्बतियों को मुआवजा देने से इनकार किया

खानाबदोशों ने चीनी सरकार से शिकायत की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ

rfa.org / संग्याल कुंचोक, २७ जून, २०२३

दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो-सोलर प्लांट के पास रहने वाले निवासियों ने रेडियो फ्री एशिया को बताया कि चीनी सरकार ने प्लांट के निर्माण से प्रभावित तिब्बती खानाबदोशों सहित सभी निवासियों को मुआवजा देने से इनकार कर दिया है।

चीनी सरकारी मीडिया ने सोमवार को बताया कि केला मेगा हाइड्रो-फोटोवोल्टिक पूरक बिजली स्टेशन ने रविवार को पूरी तरह से परिचालन शुरू कर दिया। यह एक ऐसा विशाल सौर संयंत्र है, जो १६० लाखन वर्ग मीटर या २००० से अधिक फुटबॉल मैदानों को कवर करता है। इसमें एक जलविद्युत इकाई है जो बदलते मौसम की स्थिति में ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर बनाए रखने में मदद करती है।

यह हर साल २० लाख किलोवाट-घंटे की बिजली पैदा करने में सक्षम है और केवल एक घंटे में ५५० किलोमीटर (३४० मील) की रेंज वाले १५,००० इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह से चार्ज कर सकता है।

लेकिन केला के पास रहने वाले एक तिब्बती निवासी ने आरएफए की तिब्बती सेवा को बताया कि खानाबदोश तिब्बती, जो अब सौर पैनलों के महासागर से घिरे क्षेत्र में अपने मवेशियों को चराते थे, उन्हें जबरन हटा दिया गया और बदले में कुछ भी नहीं दिया गया।

एक दूसरी जलविद्युत परियोजना का जिक्र करते हुए निवासी ने कहा, 'चीनी सरकार ने २४ जून से कार्दज़े (चीनी भाषा में गैंज़ी) के न्याचू काउंटी में जलविद्युत बांधों के साथ-साथ सबसे बड़े सौर ऊर्जा स्टेशन का संचालन शुरू कर दिया है।'

'इन बिजली संयंत्रों के निर्माण और सुविधा के लिए चीनी सरकार ने इन क्षेत्रों में भूमि हड़पने के लिए यहां के स्थानीय तिब्बतियों को विस्थापित कर दिया और अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया है।'

निवासी ने कहा कि परियोजना शुरू होने से पहले विस्थापित तिब्बतियों को कभी सूचित नहीं किया गया।

व्यक्ति ने कहा, 'इसके बजाय इन बिजली संयंत्रों के पास पुलिस तैनात कर दी गई और स्थानीय लोगों को उनके पास जाने की अनुमति नहीं थी। हालांकि अधिकारियों ने स्थानीय तिब्बतियों को बताया कि ये बिजली संयंत्र पशुधन और उनके चरागाहों के लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन अब तिब्बती खानाबदोशों को विस्थापित किया जा रहा है और अन्य स्थानों पर धकेला जा रहा है।'

एक अन्य तिब्बती निवासी ने कहा कि खानाबदोशों ने चीनी सरकार के पास शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

दूसरे व्यक्ति ने कहा, 'इस साल अप्रैल में स्थानीय तिब्बतियों ने चीनी अधिकारियों से इन परियोजनाओं को रोकने की गुहार लगाई थी। हालांकि यह बहुत स्पष्ट है कि विस्थापन और पुनर्वास का कोई विरोध संभव नहीं है और स्थानीय तिब्बतियों के पास सरकार के आदेशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।'

सैन फ्रांसिस्को स्थित तिब्बत इंटरनेशनल नेटवर्क में पर्यावरण के बारे में शोध करने वाली लोबसांग यांग्छो ने कहा कि बिजली संयंत्र तिब्बत के नाजुक पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।

उन्होंने कहा, 'चीन की नीतियां और तिब्बत में बुनियादी ढांचे का विस्तार भूकंप, बाढ़ और पारिस्थितिकी तंत्र को विभिन्न प्रकार की अपरिवर्तनीय क्षति का कारण है।'

## ◆यूएनएचआरसी ५३वां सत्र : यूएन के इतर समारोह में तिब्बत में दमन की स्थिति का मुद्दा उठाया गया

tibet.net, २२ जून, २०२३

**जिनेवा।** संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) के चल रहे ५३वें सत्र के मौके पर तिब्बत ब्यूरो- जिनेवा और सोसाइटी फॉर थ्रेटेंड पीपुल्स ने संयुक्त रूप से तिब्बत में चीन के निरंतर दमन पर प्रकाश डालने के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया।

इस इतर समारोह का विषय था- 'तिब्बतन्स रिपोर्ट ऑन द करेंट स्टेट ऑफ रिप्रेशन : ७५ इयर आफ्टर द यूनिवर्सल डिक्लरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स (मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के ७५ वर्ष बाद दमन की वर्तमान स्थिति पर तिब्बतियों की रिपोर्ट)। इस कार्यक्रम का संचालन सोसाइटी फॉर थ्रेटेंड पीपुल्स के हनो शेडलर ने किया। तिब्बत पर आयोजित इस कार्यक्रम में तिब्बत ब्यूरो के संयुक्त राष्ट्र एडवोकेसी अधिकारी काल्डेन छोमो, पूर्व तिब्बती राजनीतिक कैदी फुंटसोक न्यिड्रोन और तिब्बत एडवोकेसी गठबंधन के समन्वयक ग्लोरिया मोंटगोमरी ने अपनी बात रखी।

कार्यक्रम में बोलते हुए काल्डेन छोमो ने कहा, 'मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) को अपनाने के ७५ साल बाद भी राजनीतिक दमन, तिब्बती संस्कृति और पहचान को निगल जाना, तिब्बती लोगों से सामाजिक भेदभाव और उन्हें आर्थिक रूप से हाशिए पर ढकेल देना और चीन के नियंत्रण वाले तिब्बत में प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश जारी है। इसके अलावा, उन्होंने तिब्बत में चीन द्वारा जारी दमन पर प्रकाश डाला और संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से तिब्बत में चीन के अधिकारों के उल्लंघन को कम करने के लिए ठोस प्रयास करने का आग्रह किया।

तिब्बत की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली पूर्व महिला राजनीतिक कैदियों में से एक फुंटसोक न्यिड्रोन ने १९८९ से २००४ तक जेल में रहने के दौरान चीनी अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार और विभिन्न प्रकार की यातनाओं का अपना प्रत्यक्ष अनुभव बयां किया। उन्होंने कहा कि तिब्बती संस्कृति, पहचान और भाषा पर लगातार बढ़ते दमन के कारण तिब्बत के हालत खराब होते जा रहे हैं। उन्होंने तिब्बत के लिए लगातार अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन और तिब्बत में राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए समर्थन की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय के समर्थन के कारण वह चीनी दमन से मुक्त होने और तिब्बत पर बोलने में सक्षम हो पाई हैं। उन्होंने तिब्बतियों की स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को पूरा करने और परम पावन दलाई लामा की तिब्बत वापसी के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से समर्थन का भी आह्वान किया।

तिब्बत एडवोकेसी गठबंधन के समन्वयक ग्लोरिया मोंटगोमरी ने तिब्बत में जबरन आवासीय बोर्डिंग स्कूलों के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि पिछले साल प्रकाशित तिब्बत एक्शन इंस्टीट्यूट की एक शोध रिपोर्ट में पता चला है कि ६ से १८ वर्ष की आयु के कम से कम ९,००,००० तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों और समुदायों से अलग कर दिया गया है और आवासीय स्कूलों में रहने के लिए मजबूर किया गया है। ग्लोरिया ने कहा, 'चार और पांच साल के १,००,००० से अधिक बच्चों के अपने माता-पिता से अलग होने और सप्ताह में कम से कम पांच दिन बोर्डिंग प्री-स्कूल में रहने का भी अनुमान है।' उन्होंने उस भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक संकट पर प्रकाश डाला जो जबरन आवासीय विद्यालयों के कारण किसी भी बच्चे को होगा। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से जबरन आवासीय स्कूलों को तुरंत बंद करने और निजी तिब्बती स्कूलों को स्थापित करने की अनुमति देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि निकायों के आह्वान और आवाज को दोहराने का आग्रह किया।

## ◆ भारत-तिब्बत समन्वय संघ ने हरियाणा के सोनीपत में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 'चिंतन २०२३' आयोजित की

tibet.net, २६ जून २०२३

**हरियाणा।** भारत में तिब्बत समर्थक समूहों में से एक- भारत तिब्बत समन्वय संघ (बीटीएसएस)- ने २४ और २५ जून, २०२३ को हरियाणा के सोनीपत में 'चिंतन २०२३' शीर्षक से अपनी ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक का आयोजन किया। बीटीएसएस हरियाणा प्रांत अगुवाई में हरियाणा के सोनीपत के मुरथल स्थित प्रजापति ब्रह्माकुमारी रिट्रीट सेंटर में यह बैठक हुई। २४ जून को बैठक के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ और विशिष्ट अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री श्रीमती कविता जैन उपस्थित रहीं।

श्री धनखड़ ने अपने संबोधन में कहा कि तिब्बत के मुक्ति संघर्ष में भारत के लोगों की भावनाएं तिब्बतियों के साथ हैं और यही कारण है कि भारत सरकार ने कई बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तिब्बत का पक्ष लिया है। उन्होंने कहा कि

भारत की सोच लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है, जबकि चीन की सोच साम्राज्यवाद की है। उन्होंने कहा कि भारत तिब्बत के बिना अधूरा है क्योंकि भारत और तिब्बत प्राचीन काल से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों में एक- दूसरे से जुड़े रहे हैं।

इसके अलावा, श्री धनखड़ ने उल्लेख किया कि शांति और करुणा के वैश्विक नेता और तिब्बत के हित के लिए अहिंसक संघर्ष के नेता के रूप में परम पावन दलाई लामा के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें तिब्बती में लेखन का शौक है, विशेष रूप से परम पावन छठे दलाई लामा को लेकर उन्होंने कविता लिखी है, जिसमें एक व्यक्ति अपनी मातृभूमि में लौटने की इच्छा को दर्शाता है। चूंकि भारत तिब्बत-समन्वय संघ का मुख्य उद्देश्य तिब्बत को आज़ाद कराना है, जिस पर १९५९ में चीन ने कब्ज़ा कर लिया था। वह ल्हासा में जश्न मनाते हुए एक आज़ाद तिब्बत का सपना देखते हैं।

बीटीएसएस के निमंत्रण पर भारत- तिब्बत समन्वय कार्यालय (आईटीसीओ), नई दिल्ली की समन्वयक (कार्यवाहक) ताशी देकी और कार्यक्रम अधिकारी छोनी छेरिंग ने क्षेत्रीय तिब्बती महिला संघ, दिल्ली की अध्यक्ष फुरबू डोल्मा के साथ बैठक में भाग लिया।

सबसे पहले ताशी देकी ने भारत-तिब्बत समन्वय कार्यालय और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन (सीटीए) के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने तिब्बत के अंदर की वर्तमान स्थिति, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन, पर्यावरणीय गिरावट और दुनिया के नक्शे से तिब्बत को मिटाने के लिए सीसीपी की भयावह नीतियों पर एक सिंहावलोकन किया। उन्होंने बताया कि चीन की दमनकारी नीति का उद्देश्य केवल चीन की मुख्य हान नस्ल की राष्ट्रीय पहचान की भावना को मजबूत करना है और इसके लिए तिब्बती पहचान (संस्कृति, धर्म, भाषा, आदि) का विनाश करना या उसका चीनीकरण करना है। तब्बित के अंदर चीनी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी अभिव्यक्ति (शांतिपूर्ण प्रदर्शन) को अलगाववाद माना जाता है और मृत्युदंड तक की कठोर सजाओं तक से दंडित किया जाता है। इसके कारण तिब्बत के अंदर तिब्बतियों को शांतिपूर्ण विरोध के रूप में आत्मदाह करना पड़ रहा है और तिब्बत के अंदर न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। दुर्भाग्य से पिछले १५ वर्षों में १५८ तिब्बतियों ने आत्मदाह कर लिया है। तिब्बत में औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूलों की नीति लागू की गई है, जिसके तहत चार वर्ष की उम्र के बच्चों को उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता है और उन्हें जबरन मंदारिन भाषा में पढ़ाया जाता है। चीनी सरकार द्वारा तिब्बत में परिवारों की पूरी पीढ़ी की निगरानी के लिए तिब्बतियों का डीएनए संग्रह किया जा रहा है।

उन्होंने भारत के लिए तिब्बत के महत्व पर भी जोर दिया। उन्होंने बताया कि जब तिब्बत स्वतंत्र था, तब भारत-तिब्बत सीमा मामलों में कभी कोई बाधा नहीं थी। बल्कि दोनों देश सहजता से सह-अस्तित्व में थे। सीसीपी द्वारा तिब्बत पर कब्जे के बाद ही सीमा पर तनाव पैदा हो गया है, जिससे भारत सरकार को सीमा सुरक्षित करने में भारी खर्च करना पड़ रहा है। इसके अलावा, तिब्बत दक्षिण एशिया में प्रमुख नदियों का स्रोत है। ये नदियां कई दक्षिण एशियाई देशों की जीवन रेखा हैं। चीनी सरकार द्वारा तिब्बत में नदियों पर बांध बनाए जा रहे हैं और नदियों की धारा को मोड़कर पर्यावरण का विनाश किया जा रहा है। यह परिस्थिति विशेषकर भारत के लिए गंभीर चिंता का विषय है। इसके साथ, उन्होंने बीटीएसएस को धन्यवाद व्यक्त किया और तिब्बत और तिब्बती मुद्दे के लिए उनसे निरंतर सहयोग और समर्थन मांगा।

उन्होंने भारत के लिए तिब्बत के महत्व पर भी जोर दिया। जब तिब्बत स्वतंत्र था, तब भारत-तिब्बत सीमा मामलों में कभी कोई बाधा नहीं थी, बल्कि दोनों देश सहजता से सह-अस्तित्व में थे। सीसीपी द्वारा तिब्बत पर कब्जे के बाद ही सीमा पर तनाव पैदा हो गया है, जिससे भारत सरकार को सीमा सुरक्षित करने में भारी खर्च करना पड़ रहा है। इसके अलावा, तिब्बत दक्षिण एशिया में प्रमुख नदियों का स्रोत है जो कई दक्षिण एशियाई देशों की जीवन रेखा हैं। चीनी सरकार द्वारा तिब्बत में नदियों पर बाँध और मार्ग मोड़कर किया जा रहा पर्यावरण विनाश, विशेषकर भारत के लिए एक गंभीर चिंता का विषय है। इसके साथ, उन्होंने बीटीएसएस को धन्यवाद व्यक्त किया और तिब्बत और तिब्बती मुद्दे के लिए उनसे निरंतर सहायता और समर्थन मांगा।

श्रीमती कविता जैन ने अपने संबोधन में तिब्बती भाइयों और बहनों के प्रति अपनी एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बैठक में भाग लेने और सभी वक्ताओं को सुनने के बाद उन्हें तिब्बत के बारे में अधिक जानकारी मिली। उन्होंने अपने अनुभवों को याद करते हुए बताया कि वह हिल स्टेशनों में तिब्बती बाजारों का दौरा करती थीं, जहां उन्हें तिब्बती बहुत मेहनती और शांतिपूर्ण लोग लगते थे। उन्होंने तिब्बती संघर्ष के लिए अपने समर्थन का आश्वासन दिया और चीनी शासन से तिब्बत की शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना की।

बैठक को बीटीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. प्रयाग दत्त जुयाल, बीटीएसएस महिला अध्यक्ष प्रो. सुमित्रा कुकरेती, बीटीएसएस महिला राष्ट्रीय महासचिव डॉ. रुकमेश चौहान और आरटीडब्ल्यूए दिल्ली अध्यक्ष फुरबू डोल्मा ने भी संबोधित किया।

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक के समापन सत्र में २५ जून को बीटीएसएस यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नीरज सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। नीरज सिंह भारत के माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के पुत्र हैं। मंच पर उनके साथ बीटीएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. (डॉ.) प्रयाग दत्त जुयाल, बीटीएसएस महिला विंग की राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रो. सुमित्रा कुकरेती, बीटीएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. विवेक गुरु, बीटीएसएस के राष्ट्रीय संयोजक हेमेंद्र प्रताप सिंह तोमर, आईटीसीओ समन्वयक (कार्यवाहक) ताशी देकी और आरटीडब्ल्यूए दिल्ली की अध्यक्ष फुरबू डोल्मा विराजमान थीं।

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित पिछली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 'मंथन २०२२' के बाद पिछले छह महीनों के दौरान बीटीएसएस चैप्टर की गतिविधियों और कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बैठक में आने वाले छह महीनों में तिब्बत के लिए काम करने और तिब्बती मुद्दे को मजबूत करने के लिए बीटीएसएस की कार्य योजनाओं और कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान भारत-तिब्बत कैलेंडर तैयार कर उसके अनुरूप गतिविधियां संचालित करने, २०२४ में बीटीएसएस युवा सम्मेलन एवं महिला सम्मेलन, बीटीएसएस सदस्यों की निर्देशिका प्रकाशन, तिब्बत पर पुस्तक प्रकाशन, दून विश्वविद्यालय में तिब्बती भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने, कैलाश-मानसरोवर की मुक्ति के लिए प्रतिज्ञा और १४ नवंबर, १९६२ को भारतीय संसद द्वारा चीन-भारत युद्ध के दौरान चीन द्वारा हड़पे गए भारतीय क्षेत्रों को वापस पाने के संकल्प की याद दिलाने समेत कई प्रस्ताव पारित किए गए।

बैठक में देश के हर कोने तक पहुंचने और तिब्बत और तिब्बतियों के लिए संगठन के काम को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्य और जिला स्तर पर नए कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति पर भी चर्चा हुई।

समापन पर आईटीसीओ समन्वयक (कार्यकारी) ताशी देकी ने आरटीडब्ल्यूए दिल्ली की अध्यक्ष फुरबू डोल्मा के साथ बीटीएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी अधिकारियों और सभी सदस्यों को तिब्बत के लिए उनके समर्थन और काम के लिए पारंपरिक तिब्बती पवित्र दुपट्टा 'खटक' ओढ़ाकर सम्मानित किया। बैठक की आयोजन समिति सहित प्रजापति ब्रह्माकुमारी रिट्रीट सेंटर के सदस्यों ने भी तिब्बती प्रतिनिधियों को स्कार्फ और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया।

दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में पूरे भारत से भारत- तिब्बत समन्वय संघ के १५० से अधिक सदस्यों ने भाग लिया।

## ◆ ५३वां संयुक्त राष्ट्र एचआरसी सत्र : संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त और सदस्य देशों ने तिब्बत में चीन द्वारा मानवाधिकारों के हनन की ओर ध्यान आकर्षित किया

tibet.net, २६ जून, २०२३

जिनेवा। दुनिया भर में मानवाधिकारों की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करते हुए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के एक समूह ने तिब्बत में चीन द्वारा मानवाधिकारों के लगातार उल्लंघन पर चिंता व्यक्त की।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के वैश्विक ताजा जानकारियों के बीच उच्चायुक्त ने चीन द्वारा अधिकारों के उल्लंघन पर संधि निकायों के चीन के संदर्भ में निष्कर्षों पर प्रकाश डाला, जिसमें तिब्बती लोगों की 'पहचान को कमजोर करने वाली आत्मसातिकरण की नीतियां' भी शामिल हैं। उच्चायुक्त ने परिषद को यह भी बताया कि उच्चायुक्त का कार्यालय चीन के साथ 'आगे जुड़ाव की मांग' कर रहा है, जिसमें चीन में 'पहली बार' संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की उपस्थिति 'स्थापित' करने का महत्व भी शामिल है। इसके अलावा, उच्चायुक्त ने चीन से 'विशेष प्रक्रिया जनादेश धारकों की विशेषज्ञता लेने' का आह्वान किया।

उच्चायुक्त के वैश्विक अपडेट की प्रस्तुति के बाद ऑस्ट्रेलिया, चेक गणराज्य, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, स्वीडन और इंग्लैंड (यूनाइटेड किंगडम) सहित संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने अपने देश के बयान में तिब्बत का मुद्दा उठाया।

चीन में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए चेक गणराज्य ने चीन से अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को 'बरकरार' रखने और सभी व्यक्तियों के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की रक्षा करने और तिब्बत में चल रहे गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकार उल्लंघन को समाप्त करने का आग्रह किया। इसी तरह, यूनाइटेड किंगडम ने चीन से अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों को बनाए रखने और तिब्बत में चल रहे गंभीर और व्यवस्थित मानवाधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने सहित सभी व्यक्तियों के सार्वभौमिक मानवाधिकारों की रक्षा करने का आग्रह किया।

इसके अलावा स्विट्जरलैंड, स्वीडन और जर्मनी ने तिब्बत में मानवाधिकार की स्थिति पर 'गहरी चिंता' व्यक्त की और मानवाधिकार रक्षकों के उत्पीड़न सहित कई मुद्दे उठाए। चीन द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन पर महिलाओं के खिलाफ भेदभाव उन्मूलन समिति (सीईडीएडब्ल्यू) के निष्कर्षों को दोहराते हुए ऑस्ट्रेलिया ने तिब्बत में तिब्बती महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार पर चिंता जताई। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र के ६५ सदस्य देशों की ओर से एक संयुक्त बयान दिया, जिसमें राज्य द्वारा 'धार्मिक, भाषाई, राष्ट्रीय और नस्लीय अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के प्रति किए गए निंदनीय मानवाधिकार उल्लंघनों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। यह काम अक्सर सुरक्षा खतरे को कम करके दिखाने के घोषित उद्देश्य के साथ किया जाता है। अमेरिका द्वारा दिए गए संयुक्त बयान में अधिकारों के उल्लंघन की एक शृंखला को उद्धृत किया गया, जिसमें विशेष रूप से उन प्रथाओं को प्रतिबंधित करने और दबाने वाले कानून और नीतियां शामिल हैं जो अल्पसंख्यकों समुदाय के व्यक्तियों की पहचान और सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा हैं। अधिकारियों ने सांस्कृतिक विरासत स्थलों, कब्रिस्तानों और इनके पूजा स्थानों को नष्ट कर दिया। भाषाओं को दबाया, शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बच्चों को जबरन अपनी संस्कृति में आत्मसात किया है, आवाजाही पर गंभीर प्रतिबंध लगाया है और आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक को प्रतिबंधित किया है।

इसके अतिरिक्त विशिष्ट विषयगत मुद्दों पर एक संवादात्मक बातचीत के दौरान अमेरिका ने तिब्बत में चीनी सरकार द्वारा संचालित बोर्डिंग स्कूलों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षा पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत की सराहना की। अमेरिका ने कहा कि तिब्बत में चीनी सरकार द्वारा चलाए जा रहे जबरन बोर्डिंग स्कूलों ने लगभग दस लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से 'जबरन अलग' कर दिया है और यह मानवाधिकार संबंधी चिंताओं में गंभीर विषय है।

तिब्बत ब्यूरो और सोसाइटी फॉर थ्रेटेंड पीपुल्स ने संयुक्त रूप से तिब्बत में चीन के दमन पर प्रकाश डालने के लिए एक अतिरिक्त कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके अलावा, तिब्बती महिलाओं के खिलाफ चीन की भेदभावपूर्ण नीतियों और तिब्बत में चीन के औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूलों को ५३वें संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद सत्र में उठाया गया।

## ◆ तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने बेल्जियम में तिब्बत के पक्ष रखे

tibetanparliament.org, ३० जून २०२३

**ब्रुसेल्स।** २९ जून २०२३ को एक तिब्बती संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने बेल्जियम में वहां की विदेश मंत्रालय के विकास सहयोग के मानवाधिकार अनुभाग की अधिकारी हेलेना बर्ज से मुलाकात कर तिब्बत के पक्ष में बातें रखी। प्रतिनिधिमंडल में सांसद खेंपो जम्फाल तेनज़िन, लोपोन थुप्टेन ग्यालछेन और दोरजी छेतेन शामिल थे। उनके साथ प्रतिनिधि रिगज़िन चोएडन जेनखांग और तिब्बत ब्यूरो के सचिव थिनले वांगड्यू भी थे। बैठक के दौरान अधिकारी को चीन के कब्जे वाले तिब्बत में मानवाधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता की बिगड़ती स्थिति और तिब्बत के स्वतंत्र राष्ट्र होने के ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने उन्हें केंद्रीय तिब्बती प्रशासन की मध्यम मार्ग नीति के बारे में भी जानकारी दी, तिब्बत पर किताबें और दस्तावेज़ भेंट किए, और एक प्रश्नोत्तर सत्र रखा।

इसके बाद, प्रतिनिधियों ने बेलारूसी राजनीतिज्ञ स्वियातलाना त्सिखानौस्काया को बुलाया और उन्हें तिब्बत के पक्ष में दस्तावेज़ सौंपे।

प्रतिनिधियों ने यूरोपीय संसद के विदेश मामलों के चीन प्रभाग की प्रमुख सुश्री निकोलेटा पुस्तरला और ईईएएस के नीति अधिकारी श्री गार्ग्या के साथ भी बैठकें कीं और चीन-तिब्बती संघर्ष के समाधान पर चर्चा की।

दोपहर में प्रतिनिधिमंडल ने यूरोपीय संघ की संसद के सदस्य और कैटेलोनिया के पूर्व राष्ट्रपति कार्ल्स पुइगडमोंट से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने यूरोपीय संघ के सांसद से तिब्बत-चीन संघर्ष का मुद्दा उठाने और यूरोपीय संसद में तिब्बत मुद्दे के लिए एक विशेष समन्वयक नियुक्त करने की अपील की और तिब्बत की वर्तमान स्थिति और यूरोपीय संसद की जिम्मेदारियों से अवगत कराया।

सांसद ने उल्लेख किया कि तिब्बत के सामने आने वाली समस्याएं चीन की तिब्बती नस्ल को खत्म करने की भयानक नीति से उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने चीन के खिलाफ तिब्बतियों के लिए अपने अटूट समर्थन का आश्वासन दिया। तिब्बत और कैटेलोनिया के संघर्षों के बीच समानता बताते हुए सांसद ने यूरोपीय संसद में तिब्बत की स्थिति पर सवाल उठाने का वादा किया।

शाम को प्रतिनिधियों ने सांसद और तिब्बत हित समूह के अध्यक्ष मिकुलस पेक्सा से मुलाकात की और आम हितों के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। सांसद ने तिब्बती प्रतिनिधियों को इस उद्देश्य में अपने योगदान के बारे में जानकारी दी और अपनी भविष्य की योजनाओं से अवगत कराया।

# IMPORTANT NOTICE

Dear Readers,

Firstly, I would like to express my heartfelt appreciation for the overwhelming response and support that we have received from you since the launch of Tibbat Desh Magazine.
Tibbat Desh Magazine is the only monthly Hindi Magazine on current affairs of Tibet which includes news on teachings of His Holiness the Dalai Lama, Current grave situations inside Tibet, Events & activities in Exile and of the Tibetan Freedom movement across the globe.
You must be aware, for the past 2 years, we have been receiving complaints about delay and not obtaining the Tibbat Desh magazine on time to our readers. And also we found that many of our readers either have shifted or changed their existing postal address. Therefore to review the mailing address, we request you to assist us in providing the current postal address at the below mentioned address or email.
We would also request our readers to send their feedbacks and suggestions about the magazine.

Yours Sincerely,

Tashi Dekyi
Deputy Coordinator
India Tibet Coordination Office

# आवश्यक सूचना

**प्रिय पाठकों,**

सबसे पहले में, आप सभी का बहुत अभार व्यक्त करता हूं कि जब से तिब्बत देश मासिक पत्रिका का विमोचन हुआ आप लोगों का निरंतर समर्थन एवं शानदर भागीदारी रहा है।
तिब्बत देश, तिब्बत की पहली हिन्दी समाचार पत्रिका है, जो तिब्बत के भीतर हो रहे चीनी दमनकारी और क्रूर नीति तथा विश्व स्तर पर परमपावन दलाई लामा के मार्गदर्शन में तिब्बती आंदोलन के बारे में भारत के सरकार और लोगों में समर्थन एवं जानकारी उपलब्ध कराना है।
आप सभी को ज्ञात है कि, पिछले दो वर्षों से, हमारे पठकों का बहुत सारे शिकायतों हमारे इस कार्यलय में प्राप्त हुआ, जिनमें कई का यह कहना था कि उनको तिब्बत देश मिल नही रहा है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे पठकों का पता एवं आवास बदल गया है या वहां से रवाना हो चुका है।
इसलिए हम इस पत्रिका का इस बार समीक्षा कर रहे है। और आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि अगर आपको तिब्बत देश पत्रिका प्राप्त हो रहे है तो उसकी पुष्टी हमे तुरन्त देने की कष्ट करें। आप इसकी पुष्टी हमारे नीछे लिखे गये पता या ई–मेल पर भेज सकते है।
अतः तिब्बत देश पत्रिका के संदर्भ में अपना राय एवं सुझाव हमे समय समय पर भेजने की कष्ट करें।

सादर आपका

ताशी देकि
उप–समन्वयक, भारत तिब्बत समन्वय केंद्र
नई दिल्ली

**कार्यलय पताः** भारत तिब्बत समन्वय केंद्र, एच–10, द्वितीय मंजील, लाजपत नगर–03, नई दिल्ली–110024
**फोनः** 011–29830578
**ई–मेलः** indiatibet7@gmail.com , coordinator@indiatibet.net

June, 2023, Years: 44 Issue: 06 Regd No. : RNI 34636-79

भारत-तिब्बात मैत्री संघ की सिरमौर इकाई के सदस्यों से मिलीं सूचना और अंतरराष्ट्रीय संबंध विभाग की कलोन (मंत्री) नोरजिन डोल्मा।

भारत-तिब्बत समन्वय संघ ने हरियाणा के सोनीपत में राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक 'चिंतन २०२३'